सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 06, नई दिल्ली । मंगलवार, 12 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है।

03 आप के सत्येंद्र जैन फिर गए तिहाड जेल के अंदर
06 अब भारत होगा उच्च मध्यम आय वाला देश
08 शक्ति' के लिए जान जोखिम में डाल दूंगा, नरेन्द्र मोदी

बीएच सीरीज नंबर प्लेट क्या हैं? कौन ले सकता है, कितनी होती है बचत, जानें पूरी डिटेल्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत ने 2021 में BH (भारत) सीरीज की नंबर प्लेट पेश की। यहां हम आपको बता रहे हैं इन नंबर प्लेटों के फायदे, उन्हें कैसे हासिल करें और अन्य डिटेल्स।

संजय बाटला

नई दिल्ली। भारत में अगर आप एक अलग राज्य या शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो अक्सर आपके वाहन को नए इलाके में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का बोझिल काम भी करना पड़ता है। उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिन्हें अक्सर अपनी नौकरी के कारण शिफ्ट होना पड़ता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत ने 2021 में BH (भारत) सीरीज की नंबर प्लेटें पेश कीं। यहां हम आपको बता रहे हैं इन नंबर प्लेटों के फायदे, उन्हें कैसे हासिल करें और अन्य डिटेल्स।

बीएच नंबर प्लेट: कौन ले सकता है

बीएच, भारत का शॉर्ट फॉर्म है। यह नंबर प्लेट के देशव्यापी वैलिडिटी को दर्शाता है। जैसा कि बताया गया है, यह अनूठी नंबर प्लेट उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिनके व्यवसायों को राज्य की सीमाओं के पार लगातार शिफ्टिंग की मांग होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनमें सरकारी अधिकारी और रेगुलर ट्रांसफर का अनुभव करने वाले नौकरशाह शामिल हैं, ये नंबर प्लेट हासिल करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, डिफेंस सर्विस की मोबाइल प्रकृति के कारण, रक्षा कर्मचारी सुविधाजनक विकल्प के रूप में बीएच प्लेट का विकल्प चुनते हैं।

कई राज्यों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कर्मचारी बीएच प्लेट के साथ पुनः पंजीकरण (री-रजिस्ट्रेशन) की जटिलताओं को दरकिनार कर सकते हैं। इसी तरह, कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संचालन वाली कंपनियों में काम करने वाले निजी कंपनी के कर्मचारी बीएच सीरीज के लिए पात्र हैं। जो उन्हें शिफ्टिंग के दौरान एक आसान पंजीकरण समाधान प्रदान करते हैं।

बीएच नंबर प्लेट: इसे कैसे हासिल करें

अधिकृत डीलरों के जरिए: संभावित कार खरीदार खरीद प्रक्रिया के दौरान अपने डीलरशिप को बीएच प्लेट में अपनी दिलचस्पी के बारे में बता सकते हैं। फिर डीलरशिप Vahan पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा।

डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन: मौजूदा वाहन मालिक पात्रता प्रमाण और वाहन रिकॉर्ड सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करके सीधे Vahan पोर्टल पर BH प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीएच नंबर प्लेट: बचत

बीएच सीरीज की नंबर प्लेट हासिल करने का शुल्क वाहन की एक्स-शोरूम कीमत से जुड़ा होता है। दरें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 6 प्रतिशत से लेकर 20 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की पेट्रोल या डीजल कारों के लिए 12 प्रतिशत तक होती हैं।

हालांकि शुरुआती लागत ज्यादा लग सकती है। लेकिन यह नए राज्य में शिफ्ट होने पर रोड टैक्स का भुगतान करने की जरूरत को खत्म कर देती है। इसकी वजह से, समय के साथ पर्याप्त बचत हो सकती है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो अक्सर आते-जाते रहते हैं।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन करेगा इंजीनियर्स की फौज तैयार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज और डॉ राजीव मिश्रा ने प्रेस वार्ता में यह बताया की फेडरेशन ने नया जिम्मा उठाया है कि वह हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बच्चों को स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रदानकरेगा, इसी श्रृंखला में विगत दिनों दो प्रमुख शिक्षण संस्थानों (केआईईटी कॉलेज गाजियाबाद व मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद) में फेडरेशन ने 2 कार्यशालाएं की हैं, कॉलेज के छात्रों को ई वी क्षेत्र के अनुभवी वक्ताताओ से मिलवाया, कई दिग्गज उद्यमियों ने आकर अपना अनुभव साझा किया, इस क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल ने भूतपूर्व सलाहकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी, भारत सरकार ने सेमिनार में ईवी पॉलिसी के ऊपर जोर देते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ के अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने छात्रों से ₹एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट₹ विषय पर संवाद किया। अध्यक्ष डॉ शैलेंद्र सरोज ने

फेडरेशन का मिशन और विजन साझा किया, उन्होंने बताया कि वह बच्चों की नींव को मजबूत कैसे करेंगे, कैसे उन्हे रोजगार से जोड़ेंगे, कार्यक्रम में फेडरेशन ने गौतम बुद्ध नगर के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र झा को भी सम्मानित किया और देवेश गार्ग को सेक्रेटरी गौतम बुद्ध नगर नियुक्त किया गया, प्रतीक सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, यूनिवर्सिटी ने सभी को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपको यह बता दे की आगामी 26 अप्रैल को एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में भी फेडरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज करेगी। यह सेमिनार भारत भर में चलते रहेंगे।

फरीदाबाद की स्मार्ट सड़कें, जानें

परिवहन विशेष न्यूज

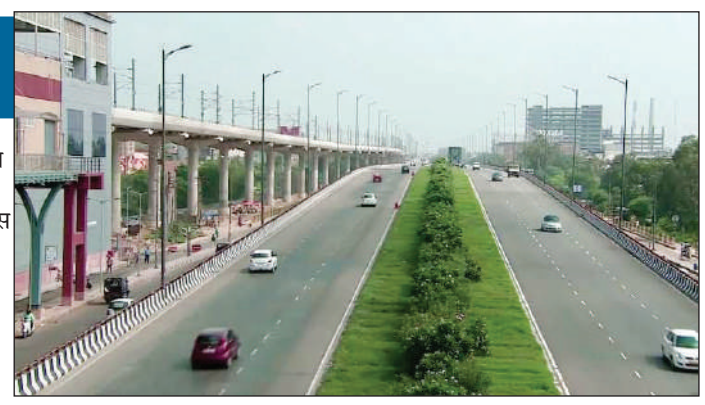

फरीदाबाद। जिला फरीदाबाद के स्मार्ट रोड है यहां पर हमारे जिले के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी मात्र 10 मीटर की दूरी पर रहते हैं इस स्मार्ट सिटी रोड पर दोनों साइड पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है एवं फुटपाथ पर भी दोनों साइड अतिक्रमण है और सेक्टर 19 साइड भी इसी तरह के बाद से बदतर हालात हैं इस सड़क के दोनों साइड रोड मार्किंग रोड सिगनेज ज़ेबरा क्रॉसिंग ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग साल 2022 में डालने के बावजूद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद आज तक इस सड़क की समस्याएं ठीक नहीं हो पाई हैं और इस सड़क पर लाइट भी नहीं चलती है हमने फिर से मुख्यमंत्री बदल दिया हमने डीसीपी ट्रैफिक एसीपी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ShO ट्रैफिक एवं जिला फरीदाबाद की ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं उनसे नीचे सारे अधिकारी बदल दिए लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं चिंता जनक स्थिति पूरे फरीदाबाद में आजकल है ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा है सीएम हरियाणा एवं डिप्टी कमिश्नर एवं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के आदेशों की पालना भी इस सड़क पर आज तक नहीं हुई है

इस स्मार्ट सड़क से भारत सरकार के प्रधानमंत्री गृहमंत्री हरियाणा सरकार के राज्यपाल मुख्यमंत्री गृहमंत्री एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एवं अन्य मंत्री एवं पुलिस के dgp सीआईडी के आल्हा अधिकारी सीएम फ्लाइंग एवं एवं अन्य जिले के बड़े-बड़े अधिकारी इस सड़क से रोजाना गुजरते हैं।

ट्रैफ़िक पुलिस दिल्ली, यातायात सलाह निर्माण कार्य के कारण भारत दर्शन पार्क जंक्शन, रिंग रोड पर यातायात प्रभावित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत दर्शन पार्क जंक्शन, रिंग रोड पर अंडरपास के निर्माण कार्य के कारण, मोती नगर से आने वाले और आर/ए पंजाबी बाग की ओर जाने वाले सभी यातायात को वशिष्ठ कुमार गुल्ला मार्ग पर डायवर्ट कर दिया गया है। रिंग रोड पर जर्सी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं.

इसके कारण, कम से कम एक महीने तक शिव दास पुरी मार्ग (करमपुरा फ्लाईओवर से भारत दर्शन पार्क के माध्यम से गोल चक्कर पंजाबी बाग की ओर) और गुरुद्वारा पंजाबी बाग और ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के पास रोड नंबर 41 पर यातायात भारी रहेगा।

- मोती नगर (करमपुरा फ्लाईओवर से भारत दर्शन पार्क के माध्यम से गोल चक्कर पंजाबी बाग की ओर) की ओर से आने वाले यात्रियों और रिंग रोड की ओर जाने का इरादा रखने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वशिष्ठ कुमार गुल्ला मार्ग लें, दाएं रोड नंबर 41 मुड़ें, दाएं मुड़ें ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क और राउंडअबाउट पंजाबी बाग की ओर बाएं मुड़ें।
- राजा गार्डन की ओर से आने वाले और राउंडअबाउट पंजाबी बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को नवनिर्मित फ्लाईओवर लेने की सलाह दी जाती है।
- धौला कुआं की ओर से आने वाले और जखीरा की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और राजा गार्डन चौक से दाहिनी ओर मुड़कर शिवाजी मार्ग की ओर जखीरा की ओर जाएं।

आम जनता और मोटर चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और अपडेट रहें।

- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in,
- फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic,
- ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic,
- इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic,
- व्हाट्सएप नंबर 8750871493, एवं
- हेल्पलाइन नंबर 1095/011-25844444।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस।

डीटीसी कर्मचारियों की दिल्ली सरकार से प्रार्थना

परिवहन विशेष न्यूज

- दिल्ली में इन इलेक्ट्रिक बसों से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे है
- इन बसों में ड्राइवर प्राइवेट कंपनियों के है और एक्सीडेंट होने पर नाम डीटीसी का खराब होता है
- इन बसों में कंडक्टर की तरह ड्राइवर भी डीटीसी के होने चाहिए, ड्राईवरो की भर्ती डीटीसी को करनी चाहिए न की प्राइवेट कंपनी को
- दिल्ली में किलोमीटर स्कीम और ड्राइवर पर ओके ड्यूटी करने का दबाव भी इन हादसों की प्रमुख वजह है।
- दिल्ली में किलोमीटर स्कीम खत्म होनी चाहिए, ड्राइवरों का मासिक वेतन फिक्स होना चाहिए और ओके ड्यूटी का नियम भी खत्म होना चाहिए, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए।

राजनीति के चक्रव्यूह में घिरी रिंग रेल, बनाना होगा दैनिक यात्रियों का मजबूत विकल्प; इन समस्याओं से होना पड़ रहा दो-चार

नई दिल्ली पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए 1975 में दिल्ली में रिंग रोड के समानांतर पटरी बिछाकर मालगाड़ी चलाने की शुरुआत की गई थी। कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी इस पर चलाई जाती थी। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में इस नेटवर्क पर 36 ट्रेनें चलने लगी थी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। यातायात जाम की समस्या से जूझ रही दिल्ली के लिए लगभग 35 किलोमीटर लंबा रिंग रेल नेटवर्क दैनिक यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। लोग कम पैसे खर्च कर राजधानी के बड़े क्षेत्र में यात्रा कर सकेंगे।

फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद व अन्य शहरों से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह लाभदायक होगा, क्योंकि रिंग रेल पर छोटे स्टेशनों के साथ ही नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन जैसे बड़े स्टेशन स्थित हैं। राजधानी में सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने में भी इससे मदद मिलेगी।

मालगाड़ियों के बोझ के चलते पैसेंजर ट्रेनें संभव नहीं

इस उपलब्ध आधारभूत ढांचे को विकसित कर इसे एनसीआर के लोगों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए गए, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार में तालमेल की कमी के कारण अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। कहा जाता है कि रिंग रेल पर मालगाड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण अधिक संख्या में पैसेंजर ट्रेनें चलाना संभव नहीं है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से मालगाड़ियों का बोझ कम हो जाएगा, जिससे अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती है। इसमें सांसदों को अपनी भूमिका निभानी होगी। वह रेल मंत्रालय के सामने इस विषय को मजबूती से रखकर इसमें आने वाली बाधा को दूर करा सकते हैं।

मालगाड़ी के लिए बिछाई गई थी समानांतर पटरी

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 1975 में दिल्ली में रिंग रोड के समानांतर पटरी बिछाकर मालगाड़ी चलाने की शुरुआत की गई थी। कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी इस पर चलाई जाती थी।

1982 में एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में इस नेटवर्क पर 36 ट्रेनें चलने लगी थी। यात्रियों की कमी के कराण आहिस्ता-आहिस्ता इनमें से अधिकांश बंद कर दी गईं। इस समय पांच जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। वह भी अधिकांश खाली रहती है। प्रतिदिन इससे लगभग 70 मालगाड़ी गुजरती है।

हजरत निजामुद्दीन से चलकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली रिंग रेल नेटवर्क पर 21 स्टेशन आते हैं। इसके चारों ओर सैकड़ों आवासीय कॉलोनी व कार्यालय स्थित हैं, फिर भी लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। अब ट्रेनों की 80 प्रतिशत सीटें खाली रहती हैं। प्रतिदिन इन ट्रेनों से लगभग साढ़े तीन हजार लोग यात्रा करते हैं।

ट्रेनें खाली रहने के कारण

स्टेशन से अन्य जगह जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धता नहीं है।

मुख्य सड़क से कई स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। सुनसान सड़कों पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है।

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का अभाव है।

स्टेशन व रेलवे लाइन के आसपास अवैध झुग्गियां स्थित हैं। कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें अपराधी ट्रेन में कोई अपराध कर झुग्गियों में छिप जाते है। इस कारण यात्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।

कम संख्या में ट्रेनें चलती हैं। इस कारण लोगों को ट्रेन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

लोकल ट्रेनों के विलंब से चलना।

समस्या के समाधान के प्रयास

रेल प्रशासन ने कई वर्ष पहले दिल्ली परिवहन विभाग से मेट्रो फीडर की तर्ज पर रिंग रेल फीडर बस सेवा चलाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ।

वर्ष 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल से पहले रिंग रेल सेवा को बेहतर बनाने को लेकर काफी चर्चा हुई थी। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और तत्कालीन रेलमंत्री ममता बनर्जी में इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।

वर्ष 2015 में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रिंग रेल विकसित करने की आवश्यकता जताई थी।

प्रदूषण की समस्या बढ़ने पर वर्ष 2016 में दिल्ली सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्री गोपाल राय ने तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर रिंग रेल के विकास की मांग की थी। बजट में भी इसे विकसित करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद रेलवे ने एक समिति बनाई थी, परंतु बात उससे आगे नहीं बढ़ी।

वर्ष 2018 में दिल्ली के सभी सातों सांसद तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर रिंग रेल को विकसित करने की मांग की थी। उसके सांसदों ने इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया।

हटाना होगा अतिक्रमण

रेलवे का कहना था कि अतिरिक्त पटरी बिछाने के लिए स्टेशनों व पटरी के आसपास से अतिक्रमण हटाना जरूरी है। दिल्ली सरकार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। स्टेशनों तक आवाजाही की समस्या दूर करने का काम भी राज्य सरकार को करना है।

रिंग रेल स्टेशनों से बढ़ानी होगी मेट्रो की कनेक्टिविटी

दिल्ली में लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल सिस्टम पर बल दिया जा रहा है। मेट्रो स्टेशनों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड से जोड़ने की कोशिश हो रही है। रिंग रेल नेटवर्क पर पड़ने वाले नौ स्टेशन या तो मेट्रो से कनेक्ट हैं या उसके नजदीक हैं। यदि अन्य स्टेशनों को भी इससे जोड़ दिया जाए तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

राइट्स से कराया गया अध्ययन

वर्ष 2016 में बजट में रिंग रेल को विकसित करने की घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स से इसे लेकर अध्ययन कराया गया। उसकी रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों के विकास, स्टेशन तक आवागमन की समस्या दूर करने, स्टेशनों व पटरियों से अतिक्रमण हटाने के सुझाव दिए थे।

मेट्रो से जुड़े रिंग रेल के स्टेशन

दिल्ली सराय रोहिल्ला (रेड लाइन)
सदर बाजार (रेड लाइन)
नई दिल्ली (यलो लाइन व एयरपोर्ट एक्सप्रेस)
प्रगति मैदान (ब्लू लाइन)
हजरत निजामुद्दीन (पिंक लाइन)
लाजपत नगर (पिंक लाइन व वायलेट लाइन)
पटेल नगर (ग्रीन लाइन)
कीर्ति नगर (ब्लू लाइन व ग्रीन लाइन)
नारायणा विहार (पिंक लाइन)

रिंग रेल नेटवर्क पर स्थित 21 रेलवे स्टेशन

दयाबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली किशनगंज, सदर बाजार, नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, प्रगति मैदान, हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, पटेल नगर, कीर्ति नगर, नारायणा विहार, इंद्रपुरी, बराड़ स्क्वायर, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, दिल्ली सफदरजंग, सरोजनी नगर और लोधी कालोनी।

कम किराया में कर सकते हैं यात्रा

रिंग रेल नेटवर्क पर 10 रुपये न्यूनतम किराया है। 12 रेलवे में न्यूनतम किराया दस रुपये में 35 किलोमीटर लंबी रिंग रेल की यात्रा पूरी की जा सकती है। वहीं, बस व मेट्रो से यात्रा करने पर 25 से 60 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम व क्लस्टर बस का किराया

नॉन एसी बस- पांच रुपये से 15 रुपये
एसी बस- 10 रुपये से 25 रुपये
मेट्रो किराया: न्यूनतम 10 रुपये और अधिकतम 60 रुपये

पैसे के साथ समय की बचत

35 किलोमीटर की यात्रा लगभग 90 मिनट में पूरी हो जाती है। राजधानी में जाम के कारण सड़क मार्ग से यात्रा करने में अधिक समय लगता है। रिंग रेल के नजदीक स्थित स्थानों पर कम समय में पहुंचा जा सकता है।

कहीं आपका बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा? इन 6 संकेतों से पहचानें, समय रहते उठाएं सही कदम वरना पड़ेगा पछताना

बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पैरेंट्स को काफी मेहनत करनी होती है. हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ता है. यदि बच्चों पर प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए तो वे गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत राह पर निकल जाते हैं. इससे उनके अंदर कई बुरी आदतें विकसित हो जाती हैं. आपका बच्चा अगर अभद्र भाषा बोलने लगे, बातों को नजरअंदाज करे तो समझ लें कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है. आपका बच्चा बुरी संगत में है और वह बिगड़ रहा है तो इन 6 संकेतों को भूलकर भी ना करें इग्नोर.

हर पैरेंट्स अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं. उसे अच्छी शिक्षा देना, जीवन में अच्छी बातें सिखाना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना जैसी बातें बच्चों को हर दिन समझाते और बताते हैं. बावजूद इसके कुछ बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं. उनकी संगत, दोस्ती-यारी अच्छी नहीं होती है. ऐसे बच्चे एक दिन मां-बाप से बातें छुपाने लगते हैं. उनसे बात-बात पर बहस करते हैं. झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. पैरेंट्स को पलट कर जवाब देते हैं. ये सभी समस्याएं टीनएजर बच्चों में अधिक देखने को मिलती है. ऐसे में 10 से लेकर 12 की उम्र वाले बच्चे पर पहले से ही ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ताकि वे टीनएज में पहुंचकर बुरी संगत के कारण बिगड़ ना पाएं. माता-पिता कुछ संकेतों पर गौर करके समझ सकते हैं कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है. जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में यहां.

आपका बच्चा बिगड़ रहा है, इन 6 संकतों से जानें

1. एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे अपने आसपास जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसे ही फॉलो करने लगते हैं. स्कूल, पार्क, ट्यूशन आदि जगहों पर वे अपने दोस्तों को जैसा करते और बोलते देखते हैं, उसे ही फॉलो करने लगते हैं. खासकर, यदि संगत सही ना हो तो बच्चों के बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि पैरेंट्स शुरू से ही उनकी बातों, हावभाव पर ध्यान दें ताकि उन्हें बिगड़ने से बचाया जा सके.

2. कुछ बच्चे किसी भी फेवरेट चीज को लेने के लिए जिद पर उतर जाते हैं. इसके लिए वे पैरेंट्स से चिल्लाकर बहस करने लगते हैं. खाना तक नहीं खाते. उन्हें हर हाल में वे चीज चाहिए होती है. 8-10 साल की उम्र के बच्चे में ये आदत अधिक देखने को मिलती है. पैरेंट्स को बच्चे की इस आदत को प्यार से समझाते हुए डील करने की जरूरत है. यदि आप भी चिल्लाकर बोलेंगे तो वे और जिद्दी बनेगा.

3. जिस काम को आप अपने बच्चे को करने से मना कर रही हों, उसे ही वो जान-बूझकर बार-बार करे तो समझ लें कि आपका लाडला या लाडली बिगड़ रही है. वो आपकी बात नहीं सुनता तो दूसरों की क्या सुनेंगा. ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप समय रहते ऐसा करने के कारणों और इस संकेत को पहचान लें.

4. यदि आप कोई भी छोटा-मोटा घर का काम करने के लिए बच्चे को बोलें और वह ना करे तो समझ जाएं कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है. आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है. ऐसा बच्चे तभी करते हैं, जब उनकी दोस्ती, संगति सही नहीं होती है. हो सकता है उसका कोई दोस्त भी अपने पैरेंट्स की बात को नहीं सुनता हो और ये ही बात आपका बच्चा भी सीख गया हो.

5. यदि आपका बच्चा बात-बात में अभद्र भाषा, गाली का इस्तेमाल करने लगा हो तो ये बच्चे के गलत संगत में रहने और बिगड़ने का एक गंभीर संकेत हो सकता है. यदि वे किसी दूसरे बच्चे से लड़ाई-झगड़ा करे, उसे थप्पड़ लगा दे, उसकी पिटाई करके घर आए तो आप अलर्ट हो जाएं. बच्चे के मुंह से किसी भी अभद्र शब्द, भाषा को सुनते ही तुरंत टोकें.

6. यदि बच्चा किसी क्लासमेट या दोस्त का कोई सामान चुरा लेता है और आपको इस बात का पता चल जाए तो उसे तुरंत समझाएं. मारने-पीटने की बजाय उसे प्यार से समझाएं कि चोरी करने का परिणाम क्या हो सकता है. यदि आपका बेटा या बेटी कोई भी किसी दूसरे बच्चे को बार-बार चिढ़ाए, उसे बुली करे तो ये भी आदत सही नहीं है.

बच्चों को एग्जाम से पहले खिलाएं 5 चमत्कारी फूड्स, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी मेमोरी, परीक्षा में नंबरों का लग जाएगा अंबार

बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके खाने-पीने पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. जब बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना मिलेगा, तब उनकी मेमोरी तेज हो जाएगी और पढ़ाई में उनका मन भी लगने लगेगा. आज आपको ऐसे ही करामाती फूड्स के बारे में बता रहे हैं.

आज के जमाने में बच्चों पर कम उम्र से ही पढ़ाई का ज्यादा दबाव रहता है. स्कूल हो या ट्यूशन, बच्चों पर हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर बना दिया जाता है. इसका बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ता है. ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में बच्चे पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन खाने-पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. इससे उनकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, बल्कि मेंटल ग्रोथ पर भी काफी असर पड़ता है. एग्जाम में सफलता की चाह के चक्कर में स्टूडेंट्स को जरूरी पोषण के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बच्चों के द्वारा खाया जाने वाला खाना सीधे उनके कॉग्निटिव फंक्शन, एनर्जी लेवल और ओवरऑल हेल्थ पर असर डालता है. पेरेंट्स को जरूरत है कि वे बच्चों के खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें, जिससे बच्चों को शरीर और दिमाग को जरूरी पोषक तत्व मिलें. ऐसा करने से वे पढ़ाई में अव्वल हो जाएंगे और उनकी मेमोरी तेज हो जाएगी.

वेलनेस कोच डॉ. नंदिता चक्रवर्ती ने TOI को बताया कि बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छी डाइट बेहद जरूरी है. बच्चों को सुबह-सुबह हेल्दी नाश्ता, लंच के साथ पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक्स दूध और फल खिलाने चाहिए. चावल या रोटी के साथ दाल और सब्जियों का एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसे बच्चे स्वाद-स्वाद में चट कर जाएं. इस तरह के संतुलित खाने से यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे की हर दिन आवश्यक विटामिन, प्रोटीन और किलोकैलोरी की मात्रा पूरी हो रही है. जिस तरह कार को चलने के लिए अच्छे फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर और दिमाग को बेस्ट काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है. सभी पेरेंट्स को बच्चों को लेकर यह बातें ध्यान रखनी चाहिए.

इन 5 फूड्स से एग्जाम में टॉप करेंगे बच्चे

– एक्सपर्ट के अनुसार ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें बच्चों का दिमाग शार्प कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें अखरोट और अलसी खिलाएं. अगर बच्चा नॉन-वेज खाता है, तो उसकी डाइट में सैल्मन फिश शामिल कर सकते हैं. इससे उसका दिमाग हेल्दी और तेज बन जाएगा.

– एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर रंगीन फलों और सब्जियों का सेवन करने से बच्चों की मेमोरी कंप्यूटर जैसी तेज हो सकती है. इन फल और सब्जियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कोशिकाओं को डैमेज से बचाते हैं और याददाश्त में सुधार करते हैं.

– कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स भी बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. ब्राउन राइस, जई और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज बच्चों को मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं. इससे बच्चों का दिमाग शार्प हो जाता है.

– प्रोटीन से भरपूर फूड्स अच्छी याददाश्त और मानसिक सतर्कता के लिए बेहद जरूरी है. चिकन, बीन्स और टोफू जैसे प्रोटीन के स्रोत न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन में सहायता करते हैं. इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ सकती है।

द्वारकाधीश के मंदिर में क्यों नहीं है रुक्मणी की मूर्ति...?

कारण है एक श्राप

द्वारकाधीश श्री कृष्ण को हम जब भी याद करते हैं तो हमारे मुंह से राधे-कृष्ण ही निकलता है।

कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है मानो ये दोनों नाम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सत्य तो ये भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो सके ये और बात है कि कुछ किवदन्तियों के अनुसार, दोनों की शादी हुई थी लेकिन ज्यादातर कथाओं के अनुसार, इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हो सका था।

द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रूक्मणी से हुआ था इसके अलावा भी उनकी कई रानियां और पटरानियां थीं। कृष्ण और रूक्मणी का रिश्ता भी आदर्श माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में उनकी प्रिय रानी रूक्मणी की एक भी मूर्ति नहीं है। वास्तव में, इसका कारण एक श्राप है जिसके कारण कृष्ण और रूक्मणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा था और इसी कारण इस मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं है।

द्वारकाधीश

द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रूक्मणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहां आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती थी।

अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये श्राप कृष्ण और रूक्मणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था।

विवाह के बाद रूक्मणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर उन्होने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि ने ये निमंत्रण स्वीकारा तो लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त रखी। उन्होने कहा कि वो उनके रथ में महल नहीं जाएंगे, वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इतंज़ाम करेंगे, कृष्ण ने ये शर्त मान तो ली लेकिन दोनों ये इस बात से परेशान थे कि वो इस शर्त को पूरा कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वो स्वंय वहां आए थे इसलिए उन्होने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया और दोनों खुद रथ में जुत गए।

काफी दूर चलने के बाद जब देवी रूक्मणी को प्यास लगी तो कृष्ण ने पैर का अंगूठा ज़मीन पर मारा और उससे निकले गंगाजल से दोनों ने प्यास बुझा ली लेकिन दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होने ऋषिवर से भी इस बारे में पूछना चाहिए। इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होने देवी रूक्मणी को 12 साल तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया और साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला है वो बंजर हो जाएगा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रूक्मणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हे इस श्राप से मुक्ति दी।

दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है

सर्वार्थ सिद्धि योग बुधादित्य और रवि योग में 24 मार्च को होगा होलिका दहन, राशि अनुसार करें होलिका दहन पूजा

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन रवि, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। होली के बाद से दीपावली तक तेजी का माहौल बना रहेगा। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए अच्छी स्थितियां बनेंगे और फायदे वाला समय रहेगा। विदेशी निवेश में भी वृद्धि होने के योग हैं।

हिंदू धर्म में होली का त्योहार दो दिवसीय होता है। इसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि होलिका दहन के दिन होली की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि रंगों का त्योहार होली इस बार 25 मार्च को मनेगा। इससे एक दिन पहले 24 तारीख को होली जलाई जाएगी। इस बार भद्रा दोष रहेगा इसलिए शाम की बजाय रात में होलिका दहन हो सकेगा। होलिका दहन के समय सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, बुध आदित्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन रवि, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। होली के बाद से दीपावली तक तेजी का माहौल बना रहेगा। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए अच्छी स्थितियां बनेंगे और फायदे वाला समय रहेगा। विदेशी निवेश में भी वृद्धि होने के योग हैं। मंदी खत्म होगी। देश में बीमारियों का संक्रमण कम होने लगेगा उद्योग बढ़ेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा समय शुरू होगा। महंगाई पर नियंत्रण बना रहेगा।

होलिका दहन पर रहेगा भद्रा का साया

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन के लिए एक घंटा 20 मिनट का ही समय रहेगा। इसकी वजह इस दिन उस दिन भद्रा प्रातः 9:55 से आरंभ होकर रात्रि 11:13 तक भूमि लोक की रहेगी। जो की सर्वथा त्याज्य है। अतः होलिका दहन भद्रा के पश्चात रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:33 के मध्य होगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य और रवि योग

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि 24 मार्च को सुबह 6:20 बजे से सुबह 11:21 बजे तक रवि योग रहेगा, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:40 बजे से रात 12:35 बजे तक रहेगा। इसी दिन रात 8:34 बजे से वृद्धि योग शुरू होगा, जो अगली रात 9:30 बजे तक रहेगा। 24 व 25 मार्च को सूर्य व बुध के कुंभ राशि में साथ रहने से बुधादित्य योग भी बनेगा, जो शुभ व मंगलकारी होगा। बुधादित्य योग से लोगों के व्यापार, शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दान-पुण्य करने का भी श्रेष्ठ फल मिलता है।

शुभ मुहूर्त

होलिका दहन तिथि- 24 मार्च 2024

भद्रा समाप्ति के बाद होलिका दहन मुहूर्त

24 मार्च 2024- रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:33

कुल अवधि- लगभग 01 घंटे 20 मिनट

होली तिथि

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ- 24 मार्च 2024 को सुबह 8:13 मिनट

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 25 मार्च 2024 को सुबह 11:44 मिनट

कैसे करें होलिका दहन

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन के बाद जल से अर्घ्य दें। शुभ मुहूर्त में होलिका में स्वयं या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से अग्नि प्रज्जवलित कराएं। आग में किसी भी फसल को सेंक लें और अगले दिन इसे सपरिवार ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है।

होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन के दिन सफेद खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के समय सिर ढंककर ही पूजा करनी चाहिए। नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। सास-बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इस दिन को भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए।

होलिका दहन की रात भी महारात्रि की श्रेणी में शामिल

भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन की रात को भी दीपावली और शिवरात्रि की भांति ही महारात्रि की श्रेणी में शामिल किया गया है। होलिका की राख को मस्तक पर लगाने का भी विधान है। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस रात मंत्र जाप करने से वे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन सुखमय बनता है, जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का अपने आप निराकरण हो जाता है।

स्कूल बस या कार में ट्रैवल करते ही बच्चों को होती है वोमिटिंग, 5 बातों का रखें ख्याल, हंसते-खेलते करेंगे सफर

अगर आपके बच्चे को भी कार या बस में ट्रैवल के दौरान वोमिटिंग आती है तो आप कुछ उपायों की मदद से उसे आराम पहुंचा सकते हैं और मोशन सिकनेस की समस्या को रोक सकते हैं.

अक्सर बच्चों में यह समस्या देखने को मिलती है कि चलती गाड़ी में ट्रैवल करने पर वे असहज महसूस करने लगते हैं और वोमिटिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है. ऐसे में वे या तो ट्रैवल नहीं करना चाहते या ट्रैवल को एन्जॉय नहीं कर पाते. लेकिन माता-पिता को समझ नहीं आता कि इस समस्या से बच्चों को किस तरह बचाया जाए. वह इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं लेकिन इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं होता. हम यहां बताते हैं कि मोशन सिकनेस क्यों होता है और बचाव के उपाय क्या हैं.

कार सिकनेस या मोशन सिकनेस क्या है

मायोक्लीनिक के मुताबिक, इसे मोशन सिकनेस या कार सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है. मोशन सिकनेस की समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग को आंतरिक कान, आंख, ज्वाइंट और मांसपेशियों की नसों से परस्पर गलत जानकारियां मिलती हैं. कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा कार की पिछली सीट पर खिड़की से बाहर देख रहा है जिसकी सीट काफी नीचे है या कोई बच्चा कार में किताब पढ़ रहा है. ऐसे में बच्चे के आंतरिक कान को गति का एहसास तो होगा, लेकिन उसकी आंखें और शरीर को नहीं. जिस वजह से पेट अपसेट होना, ठंडा पसीना आना, थकान, भूख न लगना या उल्टी होने जैसी समस्या महसूस होने लगती है. हालांकि यह कुछ बच्चों में ही क्यों होता है इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है. यह समस्या 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक देखने को मिलती है.

ये है कार सिकनेस को रोकने का तरीका

-बच्चों को कहें कि ट्रैवल के दौरान वे किताब या मोबाइल देखने की बजाय बाहर की तरफ देखें. ऐसा करने से समस्या कम होगी. बेहतर होगा कि वे ट्रैवल के दौरान सो जाएं.

-ट्रैवल से तुरंत पहले बच्चों को बहुत अधिक ना खिलाएं. अगर लंबा सफर है तो उन्हें कम मात्रा में हल्का फूड दें. मसलन, ड्राई क्रैकर्स या कुछ पीने की चीज.

-कार में पर्याप्त हवा की व्यवस्था पर ध्यान दें. बंद या सफोकेशन वाली जगह पर सिकनेस ट्रिगर का काम करता है.

-यात्रा के दौरान आप बच्चों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करें. मसलन, बात करें, गाना बजाएं या गाना गाएं. ऐसा करने से वे बेहतर महसूस करेंगे.

-अगर फिर भी बच्चे को ट्रैवल में परेशानी होती है तो आप बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें. आप उन्हें ओवर द काउंटर मेडिसीन के लिए पूछ सकते हैं.

-साथ में जिंजर कैंडी कैरी करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें मुंह में रखने दें. गहरी सांस लेने कहें इससे तुरंत आराम मिलता है. मिंट और लिवेंटर की खुशबू भी उल्टी रोकने में मदद कर सकता है.

-अगर आपके बच्चे को मोशन सिकनेस महसूस हो रहा है तो तुरंत गाड़ी रोकें और बाहर वॉक करने के लिए कहें. उतरना संभव ना हो तो उसे तुरंत पीठ नीचे करते हुए लेटने के लिए बोलें. सिर पर गीला रुमाल या तौलिया रखें. इस तरह बच्चा बेहतर महसूस करेगा.

शराब ,पैसा ,गिफ्ट ,मुफ्त और मसलमैन गुंडों के चुनावी कॉकटेल ने बनाया आयोग के लिए चुनौती

अब वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक की मियाद 46 दिन और 7 चरणों तक स्टेबल हो गए हैं। अगर देश का पहले आम चुनाव का जिक्र करें तो वह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीने तक चला था। उस वक्त वोट देने की उम्र 21 साल थी।

परिवहन विशेष न्यूज

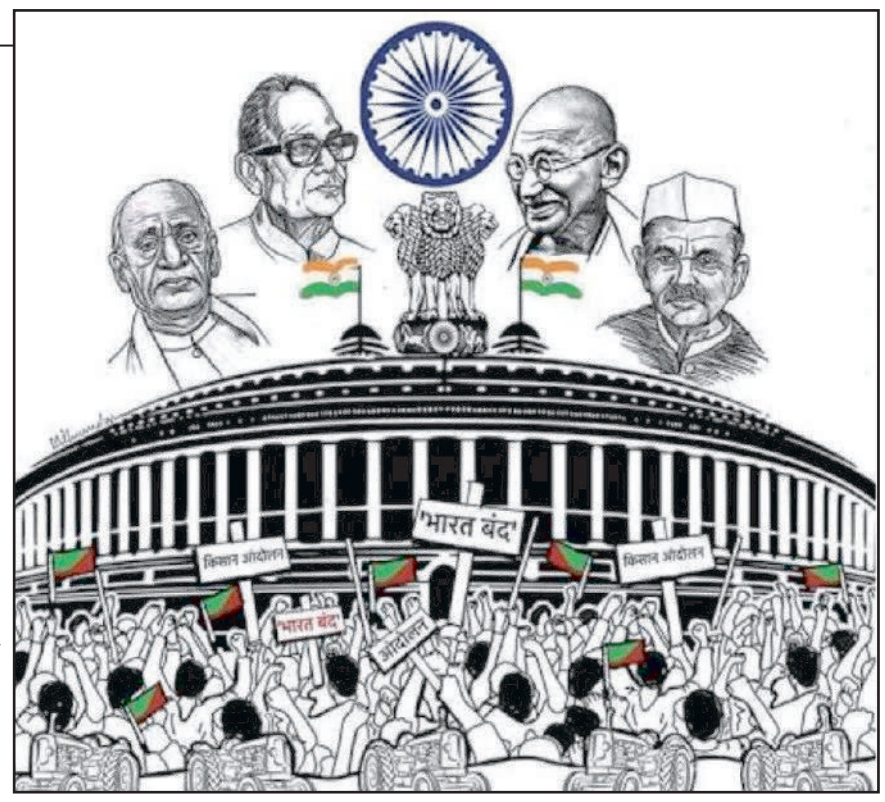

एसडी सेठी। 18 वीं लोकसभा का शंखनाद शनिवार को हो गया है ।विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र में चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष, स्वतंत्र, और भयमुक्त चुनाव कराने की चुनौतियां सिर चढ कर बोल रही हैं। टॉप पांच चुनौतियों में मसलमैन ,मनी पॉवर, शराब,गिफ्ट, मुफ्त की सौगात समेत सोशल मीडिया एवं अन्य तरीको से गलत सूचना फैलाने से रोकने के साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना भी खासा चैलेंज बनता जा रहा है। इसके अलावा हजारों करोड रूपये फूंकने के बाद भी मतदाताओं में मतदान करने के प्रति जागरूकता का प्रतिशत ग्राफ बढता दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि 2019 में हुई 67% वोटिंग का ग्राफ विज्ञापनों में करोडों फूंकने के बाद भी सिर्फ 70% तक ही पहुंच पाया है। वहीं चुनावी फेज 2004 में 4 चरणों में निपटने वाला चुनाव बढकर अब 7 चरणों में जरूर पहुंच गया है। वहीं 2009 में 16 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच 5चरणों में निपट गए थे। इसके बाद 2014 में 7 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच 9 चरणों तक पहुंच गया। अब वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक की मियाद 46 दिन और 7 चरणों तक स्टेबल हो गए हैं। अगर देश का पहले आम चुनाव का जिक्र करें तो वह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीने तक चला था। उस वक्त वोट देने की उम्र 21 साल थी। तब लोकसभा की 489 सीटें ही थी। इन सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था ।कांग्रेस ने तब 364 सीटें जीती थी ।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) दूसरी सबसे बडी पार्टी बनी थी ।भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी। उस काल के दौरान भी जन जागरूकता चुनाव आयोग के लिए सबसे बडी चुनौती थी। हालांकि तब संचार के साधन सीमित थे ।टीवी नही था। 80 % जनता शिक्षित नहीं थी। तब केवल 18 करोड वोटर थे। आयोग ने तब 3000 सिनेमाघरों के जरिये खासतौर से वोटरों को जागरूक किया जाता था। बता दें कि उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के श्याम चरण नेगी भारत के पहले मतदाता बने थे। उनका निधन हाल ही में 106 साल की उम्र में हुआ। उन्होने हिमालय प्रदेश के हाल ही में हुए विधानसभा के चुनावो मे भी वोट डाला था। उल्लेखनीय है पहले आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों के 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। आज वोटरों की संख्या बढकर 97 करोड हो गई है। राजनीतिक दलों की भी संख्येया बढकर कई गुना हो गई है। आज चुनौतीपूर्ण चुनाव धन बल,बाहुबल,संचार बल,मुफ़्त के तोहफे के कॉकटेल ने आयोग को सोचने और करने को मजबूर कर दिया है। वहीं करोडों की आबादी में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बडी संख्या में सशस्त्र बल की तैनाती और चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों की बिना दबाव के कार्य करने की चुनौती ने ही पूरी चुनावी प्रक्रिया का विश्व में सबसे बडे लोकतंत्र का डंका पिट रहा है। ये देश के चुनाव आयोग के लिए गर्व की बात है। संसार के कुल 193 देशों में से कुल 110 देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बूते पर है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र के त्योहार को बेहद ही नियोजित, और शांतिपूर्ण, तरीके से रास्ते में आने वाली सभी तरह की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम है।

24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू,चुनाव पर नजर रहेगी पैनी

परिवहन विशेष। एस.डी.सेठी।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ ही आयोग भी एक्शन मूड में आ गया है ।देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है ।वहीं चुनाव पर सख्त और पैनी नजर रखने के लिए आयोग ने देशभर में क्षेत्रीय 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए है। इसी के साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार से जुडी तमाम इजाजत लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू कर दिया है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी से आदर्श चुनाव कराने में सहयोग करने की अपील की है। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सभी 7तों लोकसभा सीटों के लिए रिटर्निंग अफसरों के आफिसों में सिंगलविंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अब इस सिंगलविंडो सिस्टम के जरिए ही चुनाव प्रचार से जुडी गतिविधियों जैसे कि पब्लिक मीटिंग,-,नुक्कड सभाए ,रैली,जुलूस,रोड शो,लाऊड स्पीकर,के इस्तेमाल और चुनाव प्रचार के लिए गाडियों के इस्तेमाल आदि के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी ।इसके लिए चुनाव प्रचार संबधी किसी इवेंट्स से कम-से-कम 49 घंटे पहले सुविधा मोबाइल ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट के एनकोर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।साथ ही तय फार्मेट में आयोजन पर होने वाले खर्च की पूरी जानकारी भी देनी होगी ।एसीपी परमिशन के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही आवेदन करना होगा ।वहीं बडे आयोजनों के मामले में 7 दिन पहले भी आवेदन दिए जा सकेगे ।एक दिन में अगर एक से अधिक इवेंट है तो उसके लिए अलग-अलग आवेदन देने होंगे ।इसी तरह अगर एक से अधिक रिटर्निंग अफसर के एरिया में कार्यक्रम होने है ,तो सभी संबंधित रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर में आवेदन देना होगा। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) परमिशंस अन्य एजेंसियों जैसे लैंड औनिंग एजेंसी, फायर,-,डिस्काम,ट्रैफिक पुलिस,आदि से क्लियरियंस लेने के बाद आवेदन को मंजूरी देगे ।सभी आवेदनों पर 'पहले आओ,पहले पाओ' बेसिस पर विचार किया जाएगा ।इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा फ्लांइग स्क्वॉड भी तैयार कर दिए गए हैं। इस संबंध में जारी नोटिस के मुताबिक रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनो के खिलाफ मामले दर्ज करने और मतदाताओ को डराने-धमकाने में जुटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलास्तर पर फ्लांइग स्क्वायड का भी गठन किया गया है।

संजय सिंह को मिली राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की अनुमति, कोर्ट ने जेल अधिकारियों को दिया ये आदेश

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए मंगलवार को संसद में पेश होने की अनुमति दी है। मालूम हो कि संजय सिंह को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए चुना गया था।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए संसद में पेश होने की अनुमति दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरोपित को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए।

10 घंटे की तलाशी के बाद हुई थी गिरफ्तार

अदालत ने कहा कि इस दौरान उन्हें फोन का उपयोग करने या अन्य आरोपित व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं है। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्टूबर, 2023 को उनके नार्थ एवेन्यू स्थित घर पर 10 घंटे की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के बाद वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता थे। ईडी ने आरोप लगाया कि एक आरोपित व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को दो करोड़ रुपये नकद दिए थे। अरोड़ा बाद में आबकारी घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सिंह ने कुछ व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया के माध्यम से आबकारी नीति में बदलाव सुनिश्चित किया था।

पुलिसऔर निगम कारिंदों ने दिल्ली की वडापॉव गर्ल को वसूली ना बढाने पर रेहडी उठाने की दे रहे धमकी

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। महिला सशक्तिकरण के नाम का ढिंढोरा पीटने, और विश्व महिला दिवस पर तरह-तरह के स्वांग करने वाली सरकार के कारिंदे दिल्ली के रानी बाग स्थित केशव महाविद्यलय के पास वडापॉव की रेहडी लगाने वाली ग्रेजुएट, साहसी, मेहनती युवती चंद्रिका गेरा दीक्षित का रो-रो कर बुरा हाल है। चंद्रिका का आरोप है कि मेहनत, इमानदारी,के बूते वह सडक किनारे पटरी में रेहडी पर वडापॉव बनाकर बेचती है। उसके हाथों बने बडापॉव का स्वाद लोगों के जबान पर ऐसा चढा कि उसकी रेहडी पर वडापॉव खाने वालों की लाइने लगने लगी है। चंद्रिका ने मुंबई के वडापॉव को मात दे दी है। लेकिन लोगों की स्वादी बढती भीड से इलाकई पुलिस से लेकर निगम के कारिंदों ने चंद्रिका को रेहडी लगाने /हटाने के लिए परेशान कर दिया है। वडापॉव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका का आरोप है कि पुलिस व नगर निगम के लोगों को पैसे देने के बाद भी वह रेहडी को हटाने की जबरदस्ती कर रहे हैं। चंद्रिका गेरा दीक्षित का आरोप है कि पुलिस व निगम वालो ने चौथ की रकम को बढाने का दबाव बना रखा है। पैसे बढा कर देने के बावजूद उनकी डिमांड बढती जा रही है। ना देने पर वह तरह से परेशान कर रहे हैं। दरअसल चंद्रिका गेरा दीक्षित सोशल मीडिया में भी वडापॉव गर्ल के नाम से खासी चर्चित हो गई है। चंद्रिका का कहना है कि उसके माता-पिता की मौत बचपन में ही हो चुकी है। वह शादी शुदा है और अपनी बुजुर्ग मौसी , पति व तीन महीने के छोटे बच्चे के साथ किराए के मकान में रहती है। 40 रूपये की एक वडापॉव की प्लेट देती है। उसी कमाई से वह रॉमैटिरियल, खरीदने के अलावा किराए के मकान व घर बच्चे का खर्च उठा रही है। चंद्रिका गेरा दीक्षित बताती है कि गेरा मेरे पति की कास्ट हैं और दीक्षित मेरे मायके का है। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली चंद्रिका की शादी दिल्ली में हुई है। पति के साथ वडापॉव की रेहडी लगाने से पहले वह हल्दीराम के एक आउटलेट्स पर जॉब किया करती थी। चंद्रिका बताती है कि अपने बच्चे की सेहत खराब होने के कारण उन्हें और उनके पति को जॉब छोड़नी पडी। इसके बाद उन्होने खाना बनाने के शौक को व्यापार में बदल दिया। और लोगों को दिल्ली में ही मुंबई के वडापॉव का स्वाद देने लगी ।लोगों के मुंह पर वडापॉव गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन पुलिस और निगम के लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। वडापॉव खाने वालों की लम्बी होती लाइन से बेचैन सरकारी कारिंदों की पैसे की डिमांड भी बढती जा रही है ।सोशल मीडिया में चंद्रिका की पुलिस प्रशासन समेत निगम कारिंदों की बावत रो-रोकर सच उगलने से सरकारी अमला खासा परेशान हो गया है। अब पुलिस व निगम के लोग उसकी रेहडी को उठाने की धमकियां दे रहे हैं। जबकि चंद्रिका का कहना है कि साथ में लगी रेहडियां बादस्तूर लगाई जा रही हैं। पुलिस व नगर निगम वालें उनको हटाने की जिदबाजी नहीं करते है। चंद्रिका का कहना है कि कथित नारी सशक्तिकरण, और महिला दिवस के नाम पर बडे-आडम्बर रचने वालों की हकीकत से रोज-ब -रोज रूबरू हो रही हूं। मगर आज तक एक महिला की परेशानी पर कारवाई करने वाला कोई नहीं आया है ।व्यवस्था की असलियत का रोना -रोते-रोते उसके हलक और आंखें सूज गई हैं।

आंखों का फ्री चेकअप कैम्प एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिनांक 11 फरवरी 2024 को सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बौद्ध विहार सी लाल चौक गोविन्द पुरी नई दिल्ली पर , सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दक्षिण पुर्वी एवं दक्षिणी दिल्ली की शाखा ने आंखों का फ्री चेकअप कैम्प एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया । इस दौरान कैम्प में आये नागरिकों को श्रीमती आयुषी गुप्ता व उनकी टीम द्वारा सीपीआर की जानकारी भी दी गई। कैम्प में करीब 300 लोगों की आखों की जांच की गई व जरूरत मन्दों को चश्मे भी दिये गये। कैम्प में निदेशक स्वास्थ्य सेवाये दिल्ली सरकार डॉक्टर वंदना बग्गा एवं श्री पी. के. राणा अतिरिक्त आयुक्त दिल्ली ब्रिगेड सहायक आयुक्त पी. डी. वर्खिया व कोर्प्स ऑफिसर श्रीमती मोनिका उपस्थित रही। अतिरिक्त मेहमान दिल्ली ब्रिगेड उपायुक्त श्री डी. एस. लामकोटी जी उपायुक्त श्री ड़ी. के. शर्मा जी, उपायुक्त श्री ओजस एस वालिया जी सहायक आयुक्त श्री एल. पी. शर्मा जी, सहायक आयुक्त श्री एन. के. भट्टी। स्कुल प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार सचिव श्री विपेंद्र कुमार व प्रधान श्री पी. एस. मौर्या जी के सहयोग से दिल्ली ब्रिगेड ने स्थानीय निवासियों को उपरोक्त सेवा प्रदान की।

खाकी से बेखौफ लूटेरों ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बनाया निशाना

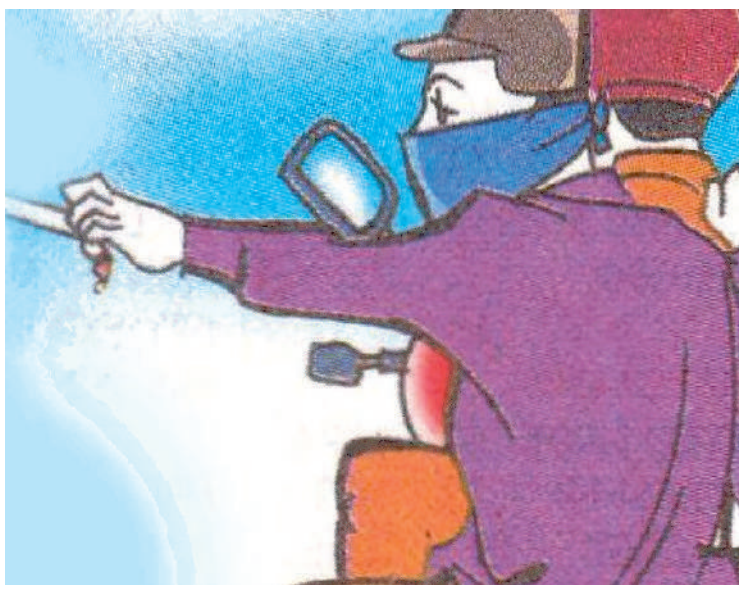

परिवहन विशेष न्यूज

एस.डी.सेठी। खाकी से बेखौफ लूटेरों के हौंसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर तक को लूटेरों ने निशाना बना डाला। नई दिल्ली स्थित वीवीआईपी एरिया चाणक्यपुरी नेहरू पार्क के एंट्री गेट पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विनोद बडोला को बदमाशों ने रिवाल्वर दिखाते हुए लूट लिया ।उल्लेखनीय है कि इंस्पेक्टर विनोद बडोला कई एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। वारदात को अंजाम देने वाले स्नैचर का जब उन्होने विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली ।और धमकी देने लगे ।बदमाशों को नहीं पता था कि वो दिल्ली पुलिस में तैनात है ।पिस्टल दिखाकर बदमाशों ने उनके गले में लटक रही गोल्ड चेन को तोड ली और फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ पलभर में ये वारदात हुई,जिसके बाद उन्होंने खुद ही बदमाशों का पीछा किया ,और उन से भिड गए ,और एक बदमाश को दबोच लिया ।जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया ।इंस्पेक्टर बडोला ने 112 नंबर डायल किया और पीसीआर को इस वारदात की सूचना दी। वारदात के वक्त खडे तमाशबीन लोगों ने कोई मदद नहीं की।

इस बीच वारदात में शामिल फरार दूसरे बदमाश की सरगर्मी के साथ तलाश की गई तो वह भी पुलिस के हत्थे चढ गया ।अब दोनों बदमाशों को पकड लिया है। हैरत की बात है कि इंस्पेक्टर होने की बात के बावजूद बेखौफ लूटेरो ने चेन पर तसल्ली से हाथ साफ कर लिया ।आसपास खडे तमाशबीन भी इंस्पेक्टर को लुटते देखते रहे।

आप के सत्येंद्र जैन फिर गए तिहाड जेल के अंदर

परिवहन विशेष।

एस.डी.सेठी। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बडा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया ,बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी दिया। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी ।सबसे बडी अदालत ने ना सिर्फ उनकी इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा ,अपीलों को खारिज किया जाता है ।याचिकाकर्ता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि जैन के वकील विवेक जैन ने सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला दे कर सरेंडर के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी ।लेकिन कोर्ट ने इस मौहलत की अपील को भी खारिज कर दिया ।और अपने आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। पूर्व मंत्री को एक बार फिर तिहाड जेल जाना होगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपति (1.47करोड की) अर्जित की। इसके बाद ईडी ने भी कथित तौर पर उनसे जुडी तीन कंपनियों की मनी लांड्रिंग जांच शुरू की। केस दर्ज करने के 5 साल बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ।जांच ऐजेंसी ने 4.60 करोड रूपये की संपत्ति भी जब्त कर ली। ईडी ने जैन पर हवाला लेन देन का आरोप लगाया।

दिल्ली-NCR में 10 ठिकानों पर ED की छापामारी, दो जगहों पर बरामद किए 65 लाख

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कैंसर की नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई ठिकानों पर छापामारी की। एजेंसी ने 10 ठिकानों की तलाशी ली है। इसके अलावा दो जगहों से 65 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पिछले सप्ताह 10 लोगों को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कैंसर की नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के कई ठिकानों पर छापामारी की। एजेंसी ने 10 ठिकानों की तलाशी ली है। इसके अलावा दो जगहों से 65 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं।

क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पिछले सप्ताह 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अलग-अलग अस्पतालों में कीमोथेरेपी की दवा की शीशियों में कैंसर की दवा के नाम पर एंटीफंगल दवा भरकर बेचते थे। इस रैकेट के तार दिल्ली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार से जुड़े हैं। एक आरोपित बीएचयू आइआइटी से बीटेक कर चुका है। इस मामले में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल की संलिप्तता भी सामने आ चुकी है।

वाहनों की चोरी कर दिल्ली-NCR में बेचते थे पार्ट्स, 2 चोर गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिल बरामद

वाहन चोर की पहचान चेतन और अरविंद जैन के रूप में हुई है। दोनों आरोपित वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स अलग कर दिल्ली-एनसीआर में बेचते थे। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज 10 मामलों को सुलझाने का दावा कर रही है।

दिल्ली। दिल्ली की स्वरूप नगर थाना पुलिस ने दो वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की दस मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस इसके अन्य साथियों का पता लगा रही है। जांच के दौरान पता चला कि पहले ये वाहनों की चोरी करते थे, फिर पार्ट्स अलग कर इसे बेच देते थे। बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार वाहन चोर की पहचान चेतन और अरविंद जैन के रूप में हुई है। इसे पकड़ने के लिए एसएचओ स्वरूप नगर की देखरेख में एक टीम गठित की गई। इस दौरान तकनीकी निगरानी और गुप्त मुखबिर से जानकारी मिली कि चेतन स्वरूप नगर के डीसीएम कॉलोनी में रहता है।

साथियों की मदद से बेच देते थे पार्ट्स: पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, आरोपित चेतन को उसके घर से पकड़ लिया। इसके घर से मोटरसाइकिल के कई पार्ट्स भी मिले हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि पहले यह मोटरसाइकिल की चोरी करता था। फिर अपने साथियों की मदद से पार्ट्स अलग कर बेच देते थे।

कार की टक्कर से बाइक सवार कंपनी कर्मी की मौत, ड्यूटी के बाद बाइक से लौट रहा था घर

परिवहन विशेष न्यूज

अलीपुर गांव के पास कार की टक्कर से बाइक सवार दो कम्पनी कर्मी घायल हो गया। उपचार के दौरान रविवार रात एक कर्मचारी की मौत हो गई। सोहना गुरुग्राम रोड पर गांव अलीपुर के पास पीछे से आई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक सवार दोनों घायलों को आसपास के लोगों ने निजी अस्पताल में पहुंचाया।

गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव के पास कार की टक्कर से बाइक सवार दो कम्पनी कर्मी घायल हो गया। उपचार के दौरान रविवार रात एक कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गौतमबुद्ध नगर के जेवर निवासी रणवीर सिंह ने बताया कि वह वर्तमान में गुरुग्राम के खांडसा में रहते हैं और नूंह की एक कंपनी में काम करते हैं। उनके साथ बंगाल के उत्तर 24 परगना निवासी अनवर अली भी काम करते थे। अनवर गुरुग्राम में गाडौली खुर्द गांव में रहता थे। दोनों लोग शनिवार रात ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे।

बाइक पर सवार थे दो लोग

सोहना गुरुग्राम रोड पर गांव अलीपुर के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक सवार दोनों घायलों को आसपास के लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

अनवर की हालत गंभीर होने पर उन्हें गुरुग्राम नागरिक अस्पताल रेफर किया गया। यहां उपचार के दौरान रविवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनवर के स्वजन को सूचना दी है।

तोड़ी जाएगी 145 किमी सड़क, चार लाख लोगों के आवागमन पर होगा असर; विरोध में उतर आए लोग

परिवहन विशेष न्यूज

मोहन नगर जोन में सीवर लाइन बिछाने में 145 किलोमीटर सड़क तोड़ी जा रही है। एक तरफ लोगों को सीवर लाइन का फायदा मिलेगा जबकि दूसरी ओर सड़क टूटने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। 330 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) से 68 हजार घरों को जोड़ने वाली पाइप लाइन बिछाने का काम अर्थला से शुरू किया गया है।

गाजियाबाद। मोहन नगर जोन में सीवर लाइन बिछाने में 145 किलोमीटर सड़क तोड़ी जा रही है। एक तरफ लोगों को सीवर लाइन का फायदा मिलेगा जबकि दूसरी ओर सड़क टूटने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। 330 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) से 68 हजार घरों को जोड़ने वाली पाइप लाइन बिछाने का काम अर्थला से शुरू किया गया है।

मोहन नगर जोन में घरों का पानी हरनंदी नदी में गिरता है। ऐसे में हरनंदी प्रदूषित हो रही है। यहां सीवर लाइन नहीं है। जल निगम द्वारा सीवर लाइन और एसटीपी के लिए 330 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम शुरू किया गया है।

अर्थला से शुरू हुआ काम

145 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने का काम अर्थला से शुरू किया गया है। अर्थला की सड़कों पर बुलडोजर से खोदाई कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लाइन बिछाने के बाद गड्ढे में मिट्टी भरकर छोड़ा जा रहा है। सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है।

कुछ सड़कें तो एक माह पहले ही बनाई गई थीं। 145 किलोमीटर सड़क टूटने से चार लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। स्थानीय निवासी रमेश का कहना है कि कई साल तक शिकायत करने के बाद एक माह पहले उनकी कालोनी की सड़क बनी थी। पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से सड़क को तोड़कर छोड़ दिया गया है। सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है।

सड़क नहीं बनाने का विरोध

पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करने का लोग विरोध कर रहे हैं। अर्थला के राजीव ने बताया कि सड़क तोड़ने के बाद उन्हें बनाने की जिम्मेदारी कोई अधिकारी नहीं ले रहा है। यदि सड़कों को नहीं बनाया गया तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे।

पाइपलाइन बिछाने से होगा फायदा

एसटीपी का शोधित पानी का प्रयोग छिड़काव और ग्रीन बेल्ट व पार्क की सिंचाई के काम में लिया जाएगा। नालों का पानी सीधा हरनंदी में नहीं गिरेगा। इससे हरनंदी नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। शोधित पानी से सिटी फोरेस्ट में पैड़-पौधों की सिंचाई भी होगी। इस पानी से सड़कों का छिड़काव भी किया जाएगा।

तोड़ने के तुरंत बाद बनाने से सड़क धंस जाती है। कुछ दिन बाद सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू करेंगे।

-अरुण प्रताप, एक्सईएन, जल निगम

एल्विश यादव से जेल में पिता ने की मुलाकात, तनाव में बीता यूट्यूबर का पहला दिन

गौतमबुद्ध नगर की जेल में बंद एल्विश यादव का पहला दिन तनाव भरा रहा है। दिन में अधिकतर समय वह बैरक में ही टहलता रहा। सोमवार को उसके पिता एल्विश से मिलने पहुंचे। उससे मिलने के लिए एल्विश के पिता राम अवतार सहित कुछ अन्य ने अर्जी लगाई थी। हालांकि सिर्फ पिता की ही अर्जी स्वीकार की गई थी।

ग्रेटर नोएडा। प्रशंसकों से घिरे रहने वाले एल्विश यादव को जेल में उच्च सुरक्षा बैरक वाली अंडा सेल में रखा गया है। जेल में उनका पहला दिन तनाव में बीता। जेल में उनसे पिता राम अवतार ने मुलाकात की। मिलने के लिए कुछ अन्य लोगों ने भी अर्जी लगाई थी। हालांकि, अन्य किसी की मुलाकात नहीं हो सकी।

हाई सिक्योरिटी बैरक में है एल्विश

एल्विश यादव प्रकरण पिछले कुछ माह से राष्ट्रीय स्तर पर छाया रहा। बड़े मामले को देखते हुए जेल प्रबंधन भी पूरी सतर्कता बरत रहा है। जेल में उसकी सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। उसे जेल में बनाए गए हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। छोटे आकार के एक बैरक में एक बंदी ही रखा जाता है। जेल में हाई सुरक्षा में अभी तक दस बंदी थे।

एल्विश के पहुंचने से संख्या बढ़कर 11 हो गई है। रात में एल्विश को काफी देर तक नींद नहीं आई। सुबह वह जल्दी उठ गया। अंडा बैरक में ही टहलकर दिन काटा, उसने किसी अन्य से बात भी नहीं की। भोजन में उसे जेल में बना खाना दिया गया, खाना काफी देर बाद खाया। उससे मिलने के लिए एल्विश के पिता राम अवतार सहित कुछ अन्य ने अर्जी लगाई थी।

पिता से मुलाकात के दौरान तनाव में रहा एल्विश

हालांकि, जेल प्रबंधन ने सिर्फ पिता की अर्जी को ही स्वीकार किया। पिता से मिलने के दौरान भी उनके चेहरे पर तनाव दिखा। जेलर जेपी तिवारी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से एल्विश को उच्च सुरक्षा बैरक में रखा गया है। दिन में अधिकतर समय वह बैरक में ही टहलता रहा।

सड़क हादसे में जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग असिस्टेंट की मौत

न्यू लिंक रोड पर डीपीएस चौराहे के पास सड़क पर पत्थर की वजह से हुए सड़क हादसे में जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग असिस्टेंट की मौत हो गयी। बाइक सवार उनका साला घायल हो गया। हादसा शनिवार दोपहर का है। मृतक 40 वर्षीय अमित चौधरी खुर्जा के सीकरी गांव निवासी थे और सुदामापुरी में रहते थे। शनिवार को वह काम पर जा रहे थे।

गाजियाबाद। न्यू लिंक रोड पर डीपीएस चौराहे के पास सड़क पर पत्थर की वजह से हुए सड़क हादसे में जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग असिस्टेंट की मौत हो गयी। बाइक सवार उनका साला घायल हो गया। हादसा शनिवार दोपहर का है। मृतक 40 वर्षीय अमित चौधरी खुर्जा के सीकरी गांव निवासी थे और सुदामापुरी में रहते थे। शनिवार को वह काम पर जा रहे थे। डीपीएस चौराहे से मेरठ तिराहे की तरफ आगे बढ़ने पर आरओबी से पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली खराब खड़ी हुई थी।

डर कर काम करता है सरकारी तंत्र

सीबीआई की तरह एसबीआई की चुनावी फंड के मामले में हुई किरकिरी से साबित हो गया है कि पिंजरे का तोता सिर्फ एक ही विभाग नहीं है। सरकारी विभाग सत्तारूढ़ दलों की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं। सत्ता बदलते ही दूसरे दलों की भाषा बोलने लगते हैं। पारदर्शिता को लेकर सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए'

सरकारी मशीनरी डंडे के जोर से काम करती है। इसका उदाहरण चुनावी बांड के खुलासे से हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इस मामले को टरकाने के प्रयास किए, किन्तु सुप्रीम कोर्ट के सामने दाल नहीं गल सकी। बांड के जरिए चुनावी चंदा देने वाले उद्योगपतियों के नाम और राशि छिपाने के एसबीआई के सारे प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। एसबीआई की मंशा थी कि इस चंदे के मामले का खुलासा जून महीने के बाद किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद इस मामले को आने वाली केंद्र सरकार संभाल सके।

एसबीआई ने इस बांड खुलासे की अवधि को लंबा खींचने के लिए कई तरह के बहाने बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया कि यदि निर्धारित तारीख तक इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई और चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को जारी किया था। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को एसबाआई ने शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं। इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के सामने एसबीआई ने घुटने टेक दिए। जिस विवरण को जुटाने के लिए जून माह तक समय मांगा जा रहा था, उसे एसबीआई ने चंद दिनों में ही पूरा कर दिखाया। इससे जाहिर है कि कार्रवाई के भय से सरकारी तंत्र तूफान की गति से काम कर सकता है। सरकारी मशीनरी में लगी जंग तभी हटती है, सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेशों की पालना करनी होती है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी सरकारी विभाग ने कोर्ट के भय के मारे घोड़े की गति से काम किया है।

कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून मंत्री और पीएमओ की दखलअंदाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा था कि सीबीआई के कई मास्टर हैं और जांच एजेंसी पिंजड़े में कैद तोते जैसी है। सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सीबीआई स्वतंत्र ही नहीं है तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है जबकि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। एसबीआई ने भी सीबीआई की तरह व्यवहार किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाने पर विवश होना पड़ा। एसबीआई फिर भी होशियारी दिखा रही है। अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने अल्फा न्यूमिरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। दरअसल यूनिक आईडी हर एक बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है। इसके जरिए आसानी से यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। चंदा देने वाले और चंदा पाने वालों की सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला था।

इन बॉन्ड्स पर पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और ये आरोप लग रहा था कि ये योजना मनी लॉन्डरिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), कॉमन कॉज और माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एडीआर के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर ने कहा कि यह फैसला काबिले-तारीफ है। इसका असर यह होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम बंद हो जाएगी और जो कॉरपोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, वो बंद हो जाएगा। इस मामले में जो पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ने खत्म की थी वो वापस आ जाएगी। इस मामले से बतौर याचिकाकर्ता जुड़े रहे माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि यह स्कीम असंवैधानिक थी और लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर) को खत्म करती थी। येचुरी ने कहा कि शुरू से ही उनकी और उनकी पार्टी की राय यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का साधन है। सीताराम येचुरी कहते हैं कि सही तो यही होगा कि पैसा वापस किया जाए क्योंकि यह स्कीम ही असंवैधानिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन कंपनियों ने यह पैसा राजनीतिक दलों को दान किया, यह उन्हें वापस न जाए। ये पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए और चुनावों के स्टेट फंडिंग की योजना को शुरू किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि उचित होगा कि हमारे लिए भी एक गोपनीयता रखी जाए। उन्होंने कहा कि कोई सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो चंदा देने वालों के खिलाफ हो जाते हैं।

इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना काम करें। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर बहुत कम फर्क पड़ता है क्योंकि चुनावी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा नकदी में आता है। यह फैसला केवल फंडिंग की पारदर्शिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ दल को धन मिलता रहेगा जबकि विपक्ष के धन का स्रोत कम हो जाएगा। न्यायालय ने बार-बार सरकार के साथ सीधे टकराव से दूर रहने का विकल्प चुना है, खासकर सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर। चूंकि य फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है तो यह बताता है कि न्यायाधीशों ने दृढ़ता से महसूस किया कि बॉन्ड योजना संवैधानिक रूप से अस्थिर थी। सीबीआई की तरह एसबीआई की चुनावी फंड के मामले में हुई किरकिरी से साबित हो गया है कि पिंजरे का तोता सिर्फ एक ही विभाग नहीं है। सरकारी विभाग सत्तारूढ़ दलों की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं। सत्ता बदलते ही दूसरे दलों की भाषा बोलने लगते हैं। दरअसल जब तक कामकाज और पारदर्शिता को लेकर कानूनी तौर पर सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक अदालतों के आदेशों की मार नौकरशाही पर पड़ती रहेगी।

सीएए पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने में क्यों जुटा हुआ है विपक्ष?

सुरेश हिंदुस्तानी

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह भी स्पष्ट है कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समाज को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है, इसके विपरीत इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं।

भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गुणा भाग का खेल प्रारंभ हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस मामले में पूर्व नियोजित राजनीति ही कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने वाला है, यह किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं करेगा। इसके विपरीत केंद्र सरकार के प्रत्येक कदम का विरोध करने वाले राजनीतिक दल इसे भारतीय मुसलमानों के विरोध में उठाया गया कदम बताने का भ्रम पैदा करने वाला रवैया बता रहे हैं। यहां एक बात यह भी स्पष्ट करने वाली है कि इस अधिनियम में भारत के मुसलमान कहीं हैं ही नहीं, फिर क्यों इस अधिनियम में मनमाफिक निहितार्थ तलाश करने की राजनीति की जा रही है? क्या इस प्रकार की राजनीति देश को मजबूत बना सकती है, यकीनन नहीं। क्योंकि जिस देश में कुतर्क की राजनीति की जाती है, वहां भ्रम का वातावरण ही निर्मित होगा। देश के राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह स्वच्छ और रचनात्मक राजनीति करके देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वह अपने एजेंडे से अलग कुछ भी नहीं कर रही है, नागरिकता का मुद्दा उसके लिए पहले से ही प्राथमिकता में रहा है। इतना ही नहीं अभी तक भाजपा नीत केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उन सभी को लेकर ही वह जनता के पास गई और भाजपा को ऐसा करने के लिए ही समर्थन मिला।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह भी स्पष्ट है कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समाज को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है, इसके विपरीत इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। वे हिन्दू सहित अन्य गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी प्रताड़ना के कारण ही वे अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन प्रताड़ित लोगों के लिए किसी भी मुस्लिम देश में शरण नहीं मिलती। इसी कारण से भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। जबकि इन देशों में मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं किया जाता। इसके विपरीत भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता इसका गलत अर्थ निकालकर भारतीय मुसलमानों को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। जबकि इस बात को यह भी भली भांति जानते हैं कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दुनिया में मुसलमानों को शरण देने वाले कई देश हैं, जबकि प्रताड़ित समाज को शरण देने के कोई भी मुस्लिम देश तैयार नहीं। इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय प्रथम दृष्टया उचित ही है।

वर्तमान में शरणार्थी और घुसपैठियों का अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है। शरण वही मांगता है जो मजबूर हो गया हो और घुसपैठ करने वाला व्यक्ति एक उद्देश्य को लेकर चलता है। आज देश के लगभग आठ राज्य ऐसे हैं जहां घुसपैठ करने वाले नागरिक भारत में रह रहे हैं। इतना ही नहीं इनको भारत में राजनीतिक संरक्षण भी आसानी से मिल जाता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी होती दिखाई देती हैं। यह केवल वोट की खातिर ही किया जा रहा है और यही तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब ये घुसपैठ करने वाले व्यक्ति अपने देश के प्रति वफादार नहीं हुए तो भारत के वफादार कैसे हो सकते हैं? इसलिए शरणार्थियों के लिए तो जगह हो सकती है, लेकिन घुसपैठियों को पनाह देना बहुत बड़े खतरे को आमंत्रण देने के समान ही कहा जाएगा।

वास्तविकता यह है ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह विरोध देश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए देश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास करने लगे हैं। मोदी का विरोध करते करते जाने अनजाने में देश का विरोध करने लगते हैं। एक समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त किया कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। कांग्रेस को आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात पर मंथन करना चाहिए था, लेकिन मंथन करना तो दूर उनको पार्टी से बाहर कर दिया। इसी प्रकार विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी गाहे बगाहे सनातन के विरोध में अप्रिय बयान देते रहे हैं। यह भी एक प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति ही कही जाएगी। ऐसी राजनीति भारत को भारत से अलग करने वाली है। यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म के बारे में गलत और विवादित बयान देने वालों के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य दलों ने कोई बयान नहीं दिया। यह एक प्रकार से उनको समर्थन देना ही कहा जाएगा।

भारत की राजनीति के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि सरकार के निर्णय का बिना किसी नीति या सिद्धांत के विरोध किया जाए। ऐसा पहले भी होता रहा है। हम जानते हैं कि राफेल मामले में भी ऐसा ही विरोध हुआ और इस मामले में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को भी लिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिज्ञ संभवतः यह भूल जाते हैं कि भारत की जनता चाहती क्या है? हम यह भी जानते हैं कि भारत की जनता राम से सीधा जुड़ाव रखती है। इसलिए यह कहा जा सकता है विपक्ष जनता के मनोभाव को समझने में अभी तक असफल ही रहा है। इसी प्रकार सीएए का मामला भी है। विपक्ष का यह कहना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता कि यह मुसलमानों के विरोध में है। इसके प्रावधान के तहत ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी या किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। जो बातें की जा रही हैं, वे केवल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। हां, इस कानून के तहत विदेशी मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिए जाने की परिकल्पना निहित है, परंतु इसमें भारतीय मुसलमान का कहीं कोई परिलक्षण नहीं है। इसलिए विपक्ष केवल भ्रमित करने की ही राजनीति कर रहा है। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए।

मारुति सुजुकी का हाइब्रिड टेक पर मास्टरस्ट्रोक, जल्द लॉन्च होगी 35 KMPL माइलेज वाली कार

मारुति की ओर से भारतीय बाजार में Fronx Facelift Next Gen Baleno और Next Gen Swift जैसी किफायती कारों को पेश किए जाने की तैयारी है। उम्मीद है कि इन कारों को हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जाएगा। इससे वाहनों का माइलेज काफी बेहतर होने वाला है। आगामी मारुति कारों को बाजार में मजबूत-हाइब्रिड सहित अन्य आईसीई कारों की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य लाभ मिल सकता है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अपना सबसे पहला Electric Vehicle पेश करने में पिछड़ रही है। हालांकि, मारुति सुजुकी ने हाइब्रिड वाहनों को लेकर बेहतरीन रणनीति बनाई है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Hybrid Technology बनेगी गेम चेंजर

मारुति की ओर से भारतीय बाजार में Fronx Facelift, Next Gen Baleno और Next Gen Swift जैसी किफायती कारों को पेश किए जाने की तैयारी है। उम्मीद है कि इन कारों को हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जाएगा। इससे वाहनों का माइलेज काफी बेहतर होने वाला है। उम्मीद है कि HEV System की मदद से 35+ Kmpl तक का माइलजे निकाला जा सकेगा।

HEV System कैसे करेगा काम?

इस सिस्टम में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर सीधे पहियों को पावर भेजेगी। एकमात्र अंतर यह है कि बैटरी को प्लग इन करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय मॉडलों में बैटरी को रिचार्ज करने के लिए ऑन-बोर्ड जनरेटर लगाए गए हैं। ये जनरेटर पेट्रोल इंजन द्वारा चलाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पेट्रोल इंजन कभी भी पहियों को सीधे नहीं चलाएगा, बल्कि ये अल्टीनेटर का काम करेगा।

Electric Car से बेहतर ऑप्शन!

आगामी मारुति कारों को बाजार में मजबूत-हाइब्रिड सहित अन्य आईसीई कारों की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य लाभ मिल सकता है। न केवल ये अविश्वसनीय रूप से कुशल होने की संभावना है, बल्कि उनके ऑन-बोर्ड जनरेटर ईवी से जुड़ी रेंज-चिंता को खत्म कर देंगे, जो इस तकनीक को इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट ऑप्शन बना सकती है।

2 लाख कीमत और सिंगल चार्ज पर 150 से 200 के बीच रेंज, जानिए कितनी खास है ये ई-बाइक

mXmoto M16 को एक क्रूजर बाइक की शेप दी गई है। इसे स्टेप्ड सिंगल पीस सीट और पिलियन के लिए बैकरेस्ट दिया गया है। कंपनी ने इसकी बैटरी को लेकर कोई जानकारी नहीं साझा की है। आप इसे केवल 1.6 यूनिट की खपत के साथ तीन घंटे से कम समय में 0 से 90 प्रतिशत तक चार्ज कर सकते हैं।

नई दिल्ली। mXmoto ने कुछ दिनों पहले mXmoto M16 इलेक्ट्रिक बाइक को 1.98 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। कंपनी की ये ई-बाइक एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आती है। इस E-Bike को हम पिछले 2 हफ्तों से चला रहे हैं। आइए, जान लेते हैं कि लगभग 2 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको क्या कुछ मिलने वाला है।

डिजाइन

mXmoto M16 को एक क्रूजर बाइक की शेप दी गई है। इसे स्टेप्ड सिंगल पीस सीट और पिलियन के लिए बैकरेस्ट दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे मेटल बॉडी के साथ

डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे क्रूजर मोटरसाइकिलों के सप्लिट फ्रेम चेसिस से इंस्पायर्ड चेसिस पर बनाया गया है।

फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक बाइक को डायनमिक एलईडी हेडलाइट, बेहतर ब्रेकिंग परफॉरमेंस के लिए ट्रिपल-डिस्क ब्रेक सिस्टम, एलईडी टर्न इंडिकेटर, स्मार्ट ऐप, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्ट, एंटी-स्किड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट, ऑन-बोर्ड नेविगेशन के साथ कॉलिंग और ब्लूटूथ साउंड सिस्टम मिलता है।

बैटरी, चार्जिंग और रेंज

कंपनी ने इसकी बैटरी को लेकर कोई जानकारी नहीं साझा की है। आप इसे केवल 1.6 यूनिट बिजली की खपत के साथ तीन घंटे से कम समय में 0 से 90 प्रतिशत तक चार्ज कर सकते हैं। ई-बाइक की बैटरी पर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है। वहीं, मोटर और कंट्रोलर पर तीन साल की वारंटी ऑफर की गई है।

परफॉरमेंस

प्रदर्शन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक होने के हिसाब से लगभग-लगभग ठीक है। स्पोर्ट मोड पर आप इसे 85 KMPH तक दौड़ा सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें, तो ये 140 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इसके अलावा, ओवरआल हैंडलिंग काफी हद तक सही है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे, तो ये भारी (Bulky) नजर आएगी, लेकिन एक बार राइड करने के बाद आप यूज्ड-टू हो जाएंगे।

हमारा फैसला

mXmoto M16 कई मायनों में बेहतर है। कंपनी को अभी इसकी टेक्नोलॉजी और कस्टमर सपोर्ट पर काम करने की जरूरत है। नॉर्मल राइड के करने पर आप इससे 150 से ज्यादा की रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट मोड में 100-120 तक ही चल पाती है।

अगर आप 1.20 लाख रुपये की एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदकर 80-100 किमी तक की डेली राइड करना चाहते हैं, तो mXmoto M16 आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है।

Paytm FASTag बंद हुआ या फिर नहीं? टोल प्लाजा पर फंसने से पहले ऐसे चेक करें

15 मार्च से पेटीएम की कई सेवाओं पर रोक लगा दी गई है जिसमें फास्टैग भी शमिल है। NHAI ने अपडेटेड लिस्ट में फास्टैग के अधिकृत जारीकर्ता के रूप में पेटीएम को हटा दिया गया। Paytm FASTag यूजर्स One vehicle one FASTag की गाइडलाइन का पालन करते हुए अन्य बैंकों और NBFC से FASTag के पक्ष में अपने अकाउंट बंद कर रहे थे।

नई दिल्ली। लगातार बढ़ रही कैशलेस पेमेंट की संख्या और Paytm की लोकप्रियता के चलते बड़ी संख्या में लोग Paytm FASTag का उपयोग करते थे। हाल में ही Paytm Payments Bank पर हुई RBI की कार्रवाई के बाद ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

15 मार्च से लग गई रोक

15 मार्च से पेटीएम की कई सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, जिसमें फास्टैग भी शमिल है। NHAI ने अपडेटेड लिस्ट में फास्टैग के अधिकृत जारीकर्ता के रूप में पेटीएम को हटा दिया गया। अगर आपके पास अभी-भी पेटीएम का फास्टैग है, तो आपको अब क्या करना है?

One vehicle one FASTag गाइडलाइन फॉलो करें

Paytm FASTag यूजर्स One vehicle one FASTag की गाइडलाइन का पालन करते हुए अन्य बैंकों और NBFC से FASTag के पक्ष में अपने अकाउंट बंद कर रहे थे। इसके अलावा, कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनका पेटीएम फास्टैग खाता बंद हो गया है या नहीं।

ऐसे करें जांच

यदि आप पाते हैं कि आपका पेटीएम फास्टैग अकाउंट बंद या सस्पेंड नहीं किया गया है, तो तुरंत डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के ग्राहक सहायता से संपर्क करना सुनिश्चित करें।

आइए, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं-

अपने स्मार्टफोन पर पेटीएम ऐप खोलें या पेटीएम वेबसाइट पर जाएं।

क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने पेटीएम खाते में लॉग इन करें।

Paytm App या Paytm वेबसाइट के अंदर FASTag सेगमेंट पर जाएं।

ऐप या वेबसाइट में अपने FASTag की स्थिति जांचने का विकल्प देखें।

अपने Paytm FASTag अकाउंट की वर्तमान स्थिति देखने के लिए ऐप या वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

BMW Motorrad ने R 1250 RT और K 1600 को बुलाया वापस, सस्पेंशन में हो रही दिक्कत के चलते लिया फैसला

जर्मन प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता ने कहा है कि ये समस्या संभवत: कंट्रोल खोने और दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस रिकॉल अभियान के कारण प्रभावित मोटरसाइकिलों में 2024 BMW R 1250 RT BMW K 1600 GT और BMW K 1600 GTL शामिल हैं। अपने रिकॉल डॉक्यूमेंट में BMW Motorrad ने कहा है कि ये मुद्दा प्रभावित मोटरसाइकिलों के इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट (ईएसए) से संबंधित है।

नई दिल्ली। BMW Motorrad ने अमेरिका में अपनी मोटरसाइकिलों के तीन अलग-अलग मॉडलों के लिए रिकॉल किया है। कंपनी ने कहा है कि इनके फ्रंट सस्पेंशन स्ट्रट के साथ संभावित समस्या है, जो ग्राहकों को परेशान कर रही है।

इन बाइक्स में दिक्कत

जर्मन प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता ने कहा है कि ये समस्या संभवतः कंट्रोल खोने और दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस रिकॉल अभियान के कारण प्रभावित मोटरसाइकिलों में 2024 BMW R 1250 RT, BMW K 1600 GT और BMW K 1600 GTL शामिल हैं।

समस्या क्या है?

अपने रिकॉल डॉक्यूमेंट में BMW Motorrad ने कहा है कि ये मुद्दा प्रभावित मोटरसाइकिलों के इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट (ईएसए) से संबंधित है। इन सस्पेंशन स्ट्रट्स में डैम्पर में वाल्व के अंदर दिक्कत आ रही है। इसके परिणामस्वरूप समय के साथ वाल्व अपने आप खुल जा रहा है, जिससे अपर्याप्त या गलत डंपिंग हो सकती है।

इस वजह से तेज गति या उबड़-खाबड़ रोड कंडीशन में वाहन चलाते समय प्रभावित मोटरसाइकिलों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि, ओईएम ने कहा कि उसे अब तक दोषपूर्ण सस्पेंशन स्ट्रट्स के कारण हुई किसी भी दुर्घटना की जानकारी नहीं है और उसने स्वेच्छा से यह रिकॉल जारी किया है।

ऐसे होगा समाधान

दोपहिया वाहन की दिग्गज कंपनी ने संभावित दोषपूर्ण सस्पेंशन स्ट्रट्स के बैच की पहचान करने का दावा किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने पहले ही अधिकृत सेवा केंद्रों को प्रभावित मोटरसाइकिलों की जांच करने और समस्या को ठीक करने के लिए इन मॉडलों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है। बीएमडब्ल्यू मोटरराड प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को सूचित करेगा और उन्हें इन्सपेक्शन और मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर में लाने के लिए कहेगा।

इस कार को खरीदो और Rolls-Royce Wraith फ्री में ले जाओ! क्रेजी डील दे रही है ये डीलरशिप

US में Naples Motorsports के नाम से एक कंपनी है। ये खुद को लग्जरी और विदेशी कारों की बिक्री सर्विसिंग व डिटेलिंग का एक्सपर्ट बताती है। इसकी ओर से हाई-प्रोफाइल कस्टमर्स को बुगाटी चिरोन की ओर रुख कराने के लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। कंपनी ने इस डील को डन करने के लिए 3.85 मिलियन डॉलर की मांगी की है।

नई दिल्ली। यूएस के फ्लोरिडा में एक कार डीलरशिप सुर्खियां बटोर रही है। डीलरशिप की ओर से Buy-one-get-one ऑफर चलाया जा रहा है। यहां तक तो आपको कहनी सामान्य लग सकती है, लेकिन पेंच तगड़ा है। दरअसल, फ्लोरिडा में इस डीलरशिप की ओर से 2021 Bugatti Chiron की खरीद पर 2018 Rolls-Royce Wraith को फ्री में दिया जा रहा है। आइए, इस बंपत स्कीम के बारे में जान लेते हैं।

कौन दे रहा बंपर ऑफर?

US में Naples Motorsports के नाम से एक कंपनी है। ये खुद को लग्जरी और विदेशी कारों की बिक्री, सर्विसिंग व डिटेलिंग का एक्सपर्ट बताती है। इसकी ओर से हाई-प्रोफाइल कस्टमर्स को बुगाटी चिरोन की ओर रुख कराने के लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप साल 2021 में बनी बुगाटी चिरोन खरीदते हैं, जो अभी तक 3,200 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी तय कर चुकी है, तो इसके साथ एक Rolls-Royce Wraith बिल्कुल फ्री में मिलेगी।

कीमत क्या है?

कंपनी ने इस डील को डन करने के लिए 3.85 मिलियन डॉलर की मांगी की है। अगर कोई कस्टमर इतना पैसा खर्च कर सकता है, तो उसे 240,000 डॉलर की रोल्स-रॉयस व्रेथ बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। इस स्पेशल यूनिट को भी लगभग 27,300 किलोमीटर चलाया जा चुका है।

ग्राहक का फायदा या मार्केटिंग स्ट्रेटजी?

ऐसे में आपको सोचना होगा कि क्या सच में एक के साथ एक कार फ्री मिल रही है या फिर ये केवल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आप निष्कर्ष चाहें जो भी निकालें, ये तो मानना ही पड़ेगा नेपल्स मोटरस्पोर्ट्स निश्चित रूप से हलचल पैदा करने में कामयाब रहा है।

अब भारत होगा उच्च मध्यम आय वाला देश

डा . जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 6 मार्च को वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत आर्थिक, वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा।

हम उम्मीद करें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देश वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2031 तक दुनिया का उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा' हाल ही में 6 मार्च को वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत आर्थिक, वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने और आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत फिलहाल 3.6 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके आगे अमरीका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। 2030-31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 6.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा और उस समय तक भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढक़र 4500 अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी और भारत उच्च मध्यम आय वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक की परिभाषा के मुताबिक दुनिया में निम्न आय वर्ग वाले 26 देश हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 83000 रुपए या उससे कम है। निम्न मध्यम वर्ग वाले 55 देश हैं जिनकी सालाना प्रति व्यक्ति आय 83000 से 332000 रुपए के बीच है। उच्च मध्यम वर्ग वाले 55 देश हैं जिनकी सालाना प्रति व्यक्ति आय 332000 से 996000 रुपए के बीच है। उच्च वर्ग वाले 79 देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 1000565 रुपए से अधिक है। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे अमरीका, चीन, जर्मनी और जापान हैं। माना जा रहा था कि भारत 2026 में जापान को पीछे कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन अब भारत और जापान की अर्थव्यवस्था में बहुत थोड़ा अंतर रह गया है। इसलिए जापान की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। 7 मार्च को दुनिया की वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आगामी 5 वर्षों तक चीन की विकास दर भारत से कम रह सकती है तथा

दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का जो वर्तमान योगदान करीब 10 फीसदी है, वह 2028 में बढक़र 16 फीसदी हो जाएगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा भारतीय सरकारी बॉन्डों को अपने सूचकांक में शामिल करने के फैसले से भारतीय ऋण बाजार को काफी मजबूती मिलेगी। इन बॉन्डों को 31 जनवरी 2025 से ब्लूमबर्ग सूचकांक में शामिल किया जाएगा। जेपी मॉर्गन के बाद ब्लूमबर्ग अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने वाला दूसरा प्रमुख वैश्विक सूचकांक प्रदाता है। जेपी मॉर्गन ने जून 2024 से भारतीय बॉन्डों को अपने सूचकांक में शामिल करने का निर्णय लिया है। भारतीय सरकारी बॉन्डों को ऐसे वैश्विक सूचकांकों में शामिल किए जाने से वैश्विक वित्तीय बाजार में भारत की वित्तीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके कई लाभ होंगे। इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेंगे, जिससे सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को चालू खाते के घाटे की भरपाई में भी आसानी होगी। यह बात महत्वपूर्ण है कि इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह रेखांकित हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है और विकास की ऐसी तेज रफ्तार से भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तथा वर्ष 2031 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में चमकते हुए दिखाई दे सकता है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4 फीसदी की तेज दर से बढ़ा है। जीडीपी की यह रफ्तार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6.5 फीसदी के अनुमान से भी अधिक रही है। जीडीपी के इस उत्साहवद्र्धक परिदृश्य के मद्देनजर अब एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6 फीसदी कर दिया है। इस समय भारतीय शेयर बाजार भी दुनियाभर में ऊंचाइयों पर रेखांकित होते हुए दिखाई दे रहा है। 7 मार्च 2024 को जो सेंसेक्स 74000 से अधिक की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, वह 2024 के अंत तक 100000 से अधिक के स्तर पर पहुंच सकता है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से बढक़र प्रदर्शन कर रही है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता बढ़ रही है और इससे भारत विकसित राष्ट्र बनने की डगर पर आगे बढऩे की अच्छी संभावनाएं रखता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक पंख लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संरचनात्मक सुधार, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और ग्रीन एनर्जी पर निर्भरता बढऩे से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे अधिक कौशल प्रशिक्षण के अभियान, बढ़ता सर्विस सेक्टर, बढ़ते निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता नए भारत के निर्माण की बुनियाद बन सकती है। इतना ही नहीं, तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण दुनिया के अधिकांश देशों की भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की ललक दिखाई दे रही है, प्रवासी भारतीयों के द्वारा लगातार प्रति वर्ष अधिक धन भारत को भेजने के साथ भारत को तकनीकी विकास के लिए मदद बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष महत्व, अमरीका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ दुनिया के जी-20 देशों में भारत की नई अहमियत और दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान भारत के विकास को तेज रफ्तार दे रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में किए गए आर्थिक और वित्तीय सुधारों के साथ-साथ कठोर प्रशासनिक निर्णयों से आर्थिक विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, वह अब आगामी लोकसभा चुनाव के बाद और तेज होते हुए दिखाई दे सकेगी।

पिछले दिनों 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 'विकसित भारत : 2047' के लिए दृष्टि पत्र और अगले पांच वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर विचार-मंथन किया गया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के बाद मई 2024 में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिवसीय एजेंडे के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। विकसित भारत के लिए यह रोडमैप दो साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। विकसित भारत के लिए इस रोडमैप के लक्ष्यों में आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जीवन को आसान बनाना, व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम उम्मीद करें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देश वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2031 तक दुनिया का उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा। विकसित देश बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा।

संपादक की कलम से

जनादेश का लोकतांत्रिक पर्व

जनादेश का लोकतांत्रिक पर्व एक बार फिर आया है। यह ऐसा पर्व है, जब देश की आम जनता वोट देकर लोकतंत्र को जिंदा रखती है और इस तरह देश के गणतंत्र और संविधान भी प्रासंगिक रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी पर्व भी व्यापक और गहरा होता है। करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 18वीं लोकसभा, विधानसभाओं और अंततः भारत सरकार का निर्वाचन करेंगे। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या हो सकता है? इतना विशाल और विराट लोकतंत्र अपने अस्तित्व के खतरे में कैसे हो सकता है? ये तथ्य और सत्य नहीं, फिजूल वाचाली है। भारत में जनादेश का यह उत्सव सम्यक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्र-निरपेक्षता, समन्वय, कमोबेश हिंसामुक्त और विवेकपूर्ण होता है, लिहाजा जनादेश को 'राष्ट्रीय' और सर्वसम्मत माना जाता है। जनादेश स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक साबित हो, लिहाजा देश में 81 दिन की 'आदर्श चुनाव आचार संहिता' लागू हो गई है। समूचे देश का प्रशासन अब चुनाव आयोग के अधीन आ गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री के स्तर पर भी किसी नई नीति की घोषणा नहीं की जा सकती। हमारा यह जनादेशी पर्व व्यापक और पारदर्शी इसलिए आंका जाता रहा है, क्योंकि दूरदराज गांव, इलाका और पहाड़ की चोटियों पर मौजूद मतदाता भी अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने को संवैधानिक आधार पर अधिकृत हैं। जो सैनिक सरहदों पर तैनात हैं अथवा जो नागरिक किसी कार्यवश अपने क्षेत्र और घर से दूर हैं, उनके मताधिकार की भी व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। अत्यधिक बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के मतदान उनके घरों पर ही सुनिश्चित कराए जाते हैं। पहली प्राथमिकता मतदान की है।

बहरहाल 18वीं लोकसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में कराया जाएगा। मतगणना 4 जून को ही सम्पन्न हो जाएगी, लिहाजा उसी दिन शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि जनादेश किसे मिला है? नई सरकार किस पार्टी और गठबंधन की बनेगी? सिर्फ जनादेश की तटस्थता और ईमानदारी के लिए आयोग 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल करेगा और 1.5 करोड़ चुनावकर्मी और सुरक्षाकर्मी जनादेश के पर्व को समानता और शांति से सम्पन्न कराएंगे। ईवीएम पर सर्वोच्च अदालत तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए ईवीएम को मान्यता दे चुकी है। अब इस पर किसी भी तरह का राजनीतिक प्रलाप बेमानी है। बहरहाल इन आंकड़ों के मद्देनजर भी हमारा आम चुनाव दुनिया में सबसे बड़ा और निष्पक्षता का उदाहरण है। अलबत्ता कुछ काली भेड़ें इस पर भी कालिख पोतने का दुस्साहस करती हैं, लेकिन वे नाकाम ही रहती हैं। जनादेश का यह सौभाग्यशाली दिन होगा, जब 1.82 करोड़ युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जनादेश की मुख्यधारा में जुड़ेंगे। चुनाव बूथ वाले उन मतदाताओं का मुंह मीठा कराएंगे। कुल 21.5 करोड़ मतदाता, जिनका आयु-वर्ग 18-29 साल है, जनादेश के पर्व में शिरकत करेंगे। अधिकतर देशों में इतनी तो आबादी भी नहीं होती और भारत के जनादेश की इतनी व्यापक ताकत है। बहरहाल इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 और 2019 में लगातार दो राष्ट्रीय जनादेश भाजपा-एनडीए को हासिल हो चुके हैं। यदि तीसरी बार भी जनादेश उन्हीं के पक्ष में रहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समकक्ष हो जाएंगे, क्योंकि लगातार तीन बार जनादेश प्राप्त करने वाला कोई अन्य प्रधानमंत्री नहीं है। जिस दौर में यह चुनाव हो रहा है, उसमें एनडीए और 'इंडिया' गठबंधन के बीच बड़े उग्र विरोधाभास हैं, नतीजतन नफरती भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक दल और नेता व्यक्तिगत आक्रमण भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में एक खास सलाह दी है और दलों को संयमी, सतर्क और समभावी होने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसा भी परामर्श दिया गया है कि जाति और धर्म पर आधारित चुनाव प्रचार न किया जाए।

राय

हिमाचल की चुनावी पड़ताल

राष्ट्रीय चुनाव की कसौटी के बीच हिमाचल की अपनी भी एक पड़ताल अवश्यंभावी दिखाई दे रही है। भले ही आज यानी 18 मार्च में वक्त की सूइयां सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के दस्तावेज तैयार हैं। राजनीतिक घटनाक्रम किसको दगा दे गया या आगे चलकर उपचुनाव किस करवट बैठेंगे, यह कयास लगाना इतना भी आसान नहीं कि हम इसे सत्ता और विपक्ष के बीच अभी तौल सकें। यह दीगर है कि क्रॉस वोटिंग से पैदा हुई अनिश्चितता के आयाम जरूर बदल रहे हैं। क्रॉस वोटिंग से उपचुनाव तक पहुंची कांग्रेस के समक्ष लोकसभा से भी बड़ी चुनौती उस परिस्थिति में होगी, अगर उपचुनाव की अनिवार्यता में पार्टी को अपना सत्ता पक्ष बरकरार रखना होगा। चुनाव की जेब में भाजपा या कांग्रेस की दौलत भरी है या एक कातिल मौका सामने आकर खड़ा हो रहा है। कहना न होगा कि भाजपा को विपक्षी मछली का शिकार करना इतना रास आ गया है कि पहले अति सुरक्षित कांग्रेस से राज्यसभा की सीट सरेआम छीन ली और अब उपचुनाव की स्थिति में फिर से सियासी श्रृंगार का अवसर मिल गया। अब छह विधायकों का बागीपन अपनी आशंका की सुबह में नए चिन्ह तलाश करेगा। धर्मशाला, सुजानपुर, लाहुल-स्पीति, बड़सर, गगरेट व कुटलैहड़ के राजनीतिक लालन पालन में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा व देवेंद्र भुट्टो क्या फिर से लाडले बन पाएंगे।

क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपचुनाव की संभावना को खारिज कर देगा या इसकी नौबत में आकर बागी विधायकों को फिर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। क्या क्रॉस वोटिंग का सम्मान समारोह आयोजित करके भाजपा अपने आंगन के फूल बदल कर, सभी के सभी पूर्व कांग्रेसियों को गले लगा लेगी। क्या भाजपा सुधीर शर्मा को लोकसभा चुनाव के मैदान पर उतारने की स्थिति में खुद को आजमा सकेगी। ऐसे में उपचुनाव में दोनों पार्टियों की आजमाइश सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं, बल्कि पार्टी के सामान्य जन तक भी होगी। भाजपा के आकाश में मोदी का प्रकाश तो है, लेकिन मुद्दों की पड़ताल में अब चुनावी बांड और इससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी रहेंगे। कांग्रेस जिन विधायकों से मुक्त होकर सत्ता का नूर बढ़ाना चाहती थी, वहां अब छह नए प्रत्याशियों की खोज, मुख्यमंत्री का ओज और सरकार के पद आबंटन का बोझ स्वयं सिद्ध होने के लिए कटिबद्ध होगा। अगर उपचुनाव की छह सीटों में कम से कम चार पर कांग्रेस जीत जाए, तो यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आभामंडल को राहत देगा, लेकिन यहां सारे उपचुनावों के साथ-साथ लोकसभा की चार सीटों की जीत में वह अपना एकछत्र साम्राज्य तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के बाद राज्य की तस्वीर में प्रभुत्व लिख सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कांग्रेस की गारंटियों से जुड़ी वचनबद्धता रही है और अपने फर्ज में वह आगे निकले हैं। राज्य की वित्तीय मजबूरियों के बावजूद प्रदेश में ओपीएस व पात्र महिलाओं को पंद्रह सौ के भुगतान की पिच पर मुख्यमंत्री एक सफल राजनीतिक बल्लेबाज स्थापित हुए हैं। चुनावी मुखरता के संदेशों में वह डीए की किस्त दे चुके हैं, जबकि आंतरिक हलचल व विरोधाभासों के बावजूद अपनी सरकार के पैगाम बांटते हुए वह कुछ विधानसभाई क्षेत्रों की विकासात्मक माप मपाई के अलावा सत्ता के पदों का आबंटन करते भी दिखाई दिए हैं। प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां 7 मई की नामांकन तारीख तक किस तरह करवट बदलती हैं, लेकिन चुनावी फेहरिस्त में हिमाचल का मूड कई संभावनाओं को टटोल रहा है।

आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं अष्टचिरंजीवी, किसी को श्राप तो किसी को वरदान से प्राप्त हुआ अमरत्व

अनन्या मिश्रा

हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर 8 चिरंजीवी हैं। जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। यह सभी चिरंजीवी पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। इनमें से कुछ को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो वहीं कुछ श्राप के कारण अमर हो गए।

अष्ट चिरंजीवी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है, जो अमर होता है यानी की उनका कभी अंत नहीं होता है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक पृथ्वी पर एक-दो नहीं बल्कि 8 चिरंजीवी मौजूद हैं। जिनका कभी अंत नहीं होगा और इनमें से कुछ को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो वहीं कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन 8 चिरंजीवी के बारे में बताने जा रहे हैं।

हनुमान जी : माता सीता द्वारा हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। जब प्रभु श्रीराम का संदेश लेकर हनुमान मां सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचे। तो मां सीता हनुमानजी की भक्ति व श्रीराम के प्रति समर्पण देख अति प्रसन्न हुईं। जिसके बाद सीताजी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। मान्यता के अनुसार, आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर वास करते हैं और प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन हैं।

अश्वत्थामा : जहां कुछ चिरंजीवी को अमरता का वरदान मिला, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। इस लिस्ट में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम शामिल है। महाभारत युद्ध के दौरान पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का रास्ता अपनाया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का निद्रा में वध कर दिया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि पृथ्वी के अंत तक घावों से लथपथ शरीर लेकर अश्वत्थामा भटकता रहेगा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। श्रीकृष्ण के श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है।

राजा बलि : प्रह्लाद भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे और राजा बलि प्रह्लाद का वंशज है। जब श्रीहरि वामन रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने आए, तो बलि ने भगवान वामन को अपना सबकुछ दान कर दिया था। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उनको अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में वास कर रहे हैं।

विभीषण : विभीषण लंकापति रावण का सबसे छोटा भाई था। विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त था और यह वरदान स्वयं श्रीराम ने दिया था। बताया जाता है कि रावण के वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी थी और साथ ही अमरत्व का वरदान दिया था। वर्तमान में भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं।

परशुराम : परशुराम भगवान शिव के परभक्त थे। साथ ही वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। परशुराम हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने परशुराम को अमरता का वरदान दिया था। वहीं महाभारत और रामायण दोनों में ही परशुराम का उल्लेख मिलता है।

कृपाचार्य : बता दें कि कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से ऋषि कृपाचार्य ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कृपाचार्य का नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल हैं। कृपाचार्य के तप की वजह से उन्हें अमरता का वरदान मिला था।

वेदव्यास : महर्षि वेदव्यास ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार हैं। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई।

विचार

न्यायिक व्यवस्था की सक्रियता व आम जनमानस

यह देश के स्वायत्त संस्थानों के असंवेदनशील व्यवहार के प्रति देश की सर्वोच्च अदालत का असाधारण आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीनस्थ संस्थाओं की निरंकुशता व असंवैधानिक कृत्यों पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा'

देश व प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, जो देश के आम नागरिकों के लोकतान्त्रिक, सामाजिक एवं मानवीय अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है या इन सभी कारकों की रक्षा एवं सुरक्षा के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वतंत्रता और समानता की पक्षधर है। सतही स्तर पर वर्तमान में देश व प्रदेश में जिन घटनाक्रमों का पटाक्षेप हो रहा है, उनकी विवेचना पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान राजनीति, राजनीतिज्ञ, प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारी लोकतंत्र की इस मूल धारणा के विपरीत अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी आदि अनुचित कार्यों में लिप्त हैं। इन कृत्यों पर अंकुश लगाने की दिशा में देश की न्यायिक व्यवस्था निरंतर प्रयासरत है। न्यायिक निर्णय, तर्क-वितर्क एवं तथ्यों की शुचिता पर आधारित होते हैं जिसके आधार पर ही माननीय न्यायाधीश अपने न्यायिक निर्णय का निर्धारण करते हैं। यह सर्वविदित है कि देश व प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश मुकदमें दो पक्षकारों के मध्य छोटे-छोटे झगड़ों, आपसी मतभेद या अहंकार, भूमि विवाद से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार के मुकद्दमों को गुण-दोष के आधार पर निर्धारित तय समय सीमा में निर्णय होना चाहिए, जिससे आम जनमानस, साधारण न्याय प्राप्त करने में, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो रहा है। अपने व्यक्तिगत विकास की गति में अवरोध उत्पन्न कर रहा है।

वर्तमान असमानता पूर्ण, भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था में, तथ्यों एवं तर्क -वितर्क को भी वादी-प्रतिवादी अपनी सुविधानुसार न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उस न्यायिक निर्णय में न्याय-अन्याय के चरित्र में कोई भी भेद नहीं रह जाता है। कालांतर से ही यह सत्यापित है कि न्याय एवं मानव निर्मित कानून दीन एवं दुर्बल अपराधी को ही दंडित करता है, जबकि समर्थ व प्रभावी अपराधी अपने धन बल, छल एवं प्रभाव से सर्वथा दोष मुक्त रहता है। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में भी आम नागरिकों मुख्यतः निर्धन, दलित एवं महिला वर्ग के लिए न्याय प्राप्त करना एक कल्पित वस्तु है। अथक मेहनत और प्रयास से जो न्याय मिलता भी है, निश्चित रूप से थका देने वाला होता है। न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है कि न्याय प्राप्ति में विलम्ब भी पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय ही माना जाता है। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश पुलिस महा निदेशक एवं ज़िला कांगड़ा के व्यवसायी के मध्य विवाद की निष्पक्ष जांच के निष्पक्षता हेतु प्रदेश पुलिस महा निदेशक व ज़िला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को उनके पद से विमुक्त करने का आदेश, प्रदेश उच्च न्यायालय का एक साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय था। इसके उपरान्त के घटनाक्रम में प्रदेश पुलिस महा निदेशक द्वारा देश की सर्वोच्च अदालत में अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, इस निर्णय को लेकर स्थगन आदेश प्राप्त करना, देश व प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में याचककर्ता की सजगता व धन बल की प्रासंगिकता या उसके महत्व को इंगित करता है। अब प्रश्न न्याय-अन्याय का नहीं है, अपितु न्यायिक व्यवस्था में भी किस प्रकार से तत्परता के साथ अपने अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है, उसको प्रमाणित करता है।

इसके विपरीत यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या देश का आम नागरिक जिसमें महिला, दलित, आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति सम्मिलित हैं, इस प्रकार से त्वरित न्याय प्राप्ति की दिशा में ऐसा प्रयास कर, न्याय प्राप्त कर सकता है? इसका स्पष्ट सा उत्तर है, कदापि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार देश व प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था का वर्तमान चरित्र है, उस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा देश की न्यायिक प्रक्रिया को सजा बताना, देश की वर्तमान न्यायिक प्रणाली की दशा को बयान करता है। देश का लचर न्यायिक ढांचा, देश व प्रदेश के न्यायालयों में लम्बित मुक़द्दमों का अत्यधिक दबाव एवं अधिवक्ताओं का आपसी गठजोड़, देश के न्यायालयों में विचाराधीन मुक़द्दमों के त्वरित निर्णय एवं समाधान में सबसे प्रमुख बाधा हैं। अपितु दोषमुक्त न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक मानकों एवं मापदंडों की पूर्ति में अप्रतिक्षित चुनौतियां एवं रुकावटें वादी-प्रतिवादी के समक्ष होती हैं। इन चुनौतियों के उपरान्त भी अनिर्णय व उचित समाधान न होने से, कोई भी मुक़द्दमा वादी-प्रतिवादी के लिए एक दिशाहीन लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जोकि न्याय प्राप्ति के मूल मंतव्य के विपरीत है। केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के महापौर पद के चुनाव के दौरान सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों के विपरीत कार्य किया गया, इस संदेहास्पद स्थिति पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही करना देश की न्यायिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रति आम जनमानस की आस्था व दृष्टिकोण को सशक्त करता है, अन्यथा इस प्रकार के असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कृत्यों में सम्मिलित नेताओं एवं अधिकारियों की निरंकुशता लोकतान्त्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की दिशा में अग्रसर रहती है।

इस प्रकरण से यह प्रमाणित होता है कि संवैधानिक संस्थाओं में प्रभावशाली व्यक्तियों के अविवेकी, असंतुलित, पूर्वाग्रह ग्रस्त निर्णय इन संस्थाओं के संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक आधारों की नींव को खंडित करने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बाण्ड के दाताओं के विवरण को सार्वजनिक करने व विवरण को 15 मार्च तक उपलब्ध करवाने का कठोर आदेश पारित करना भी उल्लेखनीय है। यह देश के स्वायत्त संस्थानों के माननीय न्यायालय व कानून के प्रति असंवेदनशील व्यवहार के प्रति देश की सर्वोच्च अदालत का असाधारण आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अधीनस्थ संस्थाओं की निरंकुशता व असंवैधानिक कृत्यों पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा।

किशन बुशैहरी

क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इन पांच बातों का रखें ध्यान, नहीं तो फंस जाएंगे कर्ज के जाल में

अगर क्रेडिट कार्ड का सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इससे आप सैलरी खत्म होने के बाद बिजली या पानी का बिल चुका सकते हैं। लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड का यूज लोग फिजूलखर्ची के लिए करने लगते हैं। इससे कर्ज के जाल में फंसने का खतरा रहता है जिससे निकलना मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं इससे बचने का तरीका।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कई बार सैलरी खत्म होने के बाद हमें शॉपिंग या किसी और काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हम इस्तेमाल करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड। बेशक यह हमारी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से काफी सुविधाजनक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल समझ-बूझकर ना किया जाए, तो यह परेशानी का सबब भी बन सकता है।

आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें किस तरह से कर्ज के जाल में फंसा सकता है और उससे बचने का क्या उपाय है?

चुकाना पड़ सकता है भारी ब्याज

क्रेडिट कार्ड पैसों की फौरी जरूरत को पूरा तो कर देता है, लेकिन अगर आप समय से बिल नहीं चुका पाते, तो आपको 30 फीसदी या इससे अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में समय पर बिल चुकाने के लिए आपको दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ सकता है और फिर आप कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे।

ऑफर-डिस्काउंट के लालच से दूरी

कई बार हमें ईकॉमर्स साइट पर काफी लुभावने ऑफर दिख जाते हैं और हम अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन, हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से किया गया खर्च कर्ज ही होता है। ऐसे में हमें हमेशा खर्च अपनी जरूरत के हिसाब से ही करना चाहिए और ऑफर के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना लें

एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखने पर उन्हें संभालने का मसला होता है। कई बार समय से बिल भरना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही, इसके साथ एनुअल फीस जैसे खर्च भी जुड़े होते हैं। एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने पर फिजूलखर्ची की लत भी लग सकती है।

ऐसे में क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए और एक से आपका काम क्यों नहीं चल सकता।

क्रेडिट स्कोर भी हो सकता है खराब

क्रेडिट कार्ड हाथ में होने पर हम आंख बंद करके खर्च करने लगते हैं। लेकिन, हमें लिमिट का 30 प्रतिशत तक ही खर्च करना चाहिए। इससे ज्यादा खर्च करने पर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है। आसान शब्दों में कहें, तो यह कर्ज पर ज्यादा निर्भर होने का संकेत है। इससे क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है।

कैश निकालना घाटे का सौदा

क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचना चाहिए। इसमें आपको ब्याज के अलावा दूसरे चार्ज भी देने पड़ते हैं, जो निकाले गए कैश के 2.5 से 3 फीसदी तक हो सकते हैं।

आपको पैसा निकालने वाले दिन से ही ब्याज देना पड़ता है। बैंक इसके लिए तगड़ा चार्ज भी वसूल सकता है, जो हर बैंक के लिए अलग-अलग होता है।

अचानक क्लोज न करवाएं कार्ड

कई बार दो क्रेडिट कार्ड होने पर लोग अचानक से एक बंद करा देते हैं। लेकिन, इससे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ सकता है। यह रेशियो पहले दो काड्र्स में बंटा था, जो अब एक ही कार्ड पर निर्भर हो जाएगा। इससे भी क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है।

सिबिल स्कोर खराब हो गया है? इन पांच तरीकों से कर सकते हैं दुरुस्त

अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बिना किसी दिक्कत के बेहतर शर्तों के साथ अच्छी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकता है। वहीं सिबिल स्कोर खराब होने पर लोन मिलने में कई परेशानियां होती है और कई बार तो बैंक सीधे मना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिबिल स्कोर कैसे चेक किया जाता है और खराब सिबिल स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं।

नई दिल्ली। हमें कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या घर बनवाना है या फिर जमीन लेनी है। ऐसे में हम पैसों का इंतजाम अमूमन लोन लेकर करते हैं। लेकिन, अगर आपको आसानी से कर्ज चाहिए, तो इसके लिए सिबिल स्कोर (CIBIL Score) अच्छा रखना होता है।

आइए जानते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और अगर यह खराब हो गया है, तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

सिबिल स्कोर क्या होता है?

Credit Information Bureau India Limited (CIBIL) एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इसे रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस मिला है और यह कंपनियों के साथ आम लोगों की कर्ज से जुड़ी गतिविधियों को ट्रैक करती है। इसकी रेटिंग को ही सिबिल स्कोर कहा जाता है।

सिबिल स्कोर या सिबिल रेटिंग एक पैमाना होता है, जिससे पता चलता है कि लोन लेने और उसे वापस चुकाने में आपका रिकॉर्ड कितना अच्छा है। यह 300 से 900 के बीच होता है। 300 से 600 का मतलब है कि आप लोन चुकाने में बहुत बुरे हैं। वहीं, 750 से 900 का सिबिल स्कोर बताता है कि आपका कर्ज लौटाने का रिकॉर्ड बेहद शानदार है।

सिबिल स्कोर खराब हो गया तो?

अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम आया, तो आपको कर्ज मिलने में मसला हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी न मिले। लेकिन, अच्छी बात यह है कि सिबिल स्कोर सुधारा भी जा सकता है। आइए जानते हैं सिबिल स्कोर सुधारने के पांच तरीके।

1. समय पर चुकाए कर्ज

अगर आप समय पर कर्ज नहीं चुकाते, तो इसका सिबिल स्कोर पर काफी बुरा असर पड़ता है। आपको EMI का पेमेंट हमेशा वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि इसमें देरी पर न सिर्फ पेनल्टी लगती है, बल्कि क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है।

2. अच्छा क्रेडिट बैलेंस बनाएं

आपके पास होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन के साथ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन का ठीकठाक तालमेल होना चाहिए। बैंक और NBFC अमूमन सिक्योर्ड लोन वालों को ज्यादा पसंद करते हैं।

अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन अधिक हैं, तो अच्छे क्रेडिट बैलेंस के लिए पहले उनका भुगतान कर देना चाहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो कोशिश करें कि उसे तय तारीख से पहले भर दें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए अच्छी योजना हो सकती है।

3. क्रेडिट कार्ड में बकाया ना रखें

अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो कोशिश करें कि उसे तय तारीख से पहले भर दें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए अच्छी योजना हो सकती है।

4. लोन का गारंटर बनने से बचें

आपको ज्वाइंट खाता खुलवाने या किसी के लोन का गारंटर बनने से परहेज करना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट करती है, तो उससे आपका भी सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। साथ ही आपको एक साथ कई लोन नहीं लेने चाहिए। अगर आप दूसरा लोन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि पहले वाला खत्म हो जाए। इससे क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

5. क्रेडिट कार्ड का यूज लिमिट में करें

अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर जल्दी बेहतर कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर महीने क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30 फीसदी ही खर्च हो। इससे ज्यादा के खर्च से जाहिर होता है कि आप बिना सोचे-समझे पैसे उड़ाते हैं और आपकी कर्ज पर निर्भरता अधिक है।

साथ ही आपको कर्ज लेते समय रीपेमेंट के लिए लंबी अवधि चुननी चाहिए। इससे EMI कम रहेगी और आपको कर्ज चुकाने के लिए लंबा वक्त मिल जाएगा। आपके डिफॉल्ट करने की गुंजाइश भी कम रहेगी और आपका सिबिल स्कोर अपनेआप बेहतर होता जाएगा।

क्रेडिट स्कोर सुधारने में कितना वक्त लगेगा?

इसका जवाब काफी हद तक आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप समय पर कर्ज चुकाते हैं और क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर 4 से 13 महीनों में बेहतर हो सकता है। लेकिन, मूल मंत्र वही है कि आपको पैसा खर्च करने के मामले में अनुशासित होना पड़ेगा।

ऐसे चेक करें CIBIL Score...

- https://www.cibil.com/पर जाएं।
- 'Get your CIBIL Score' पर क्लिक करें।
- अपना नाम, ई-मेल आईडी और पासवर्ड टाइप करें। एक आईडी प्रूफ सबमिट करें। फिर पिन कोड, जन्म तिथि और फोन नंबर दर्ज करें।
- फिर 'accept and continue' पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी मिलेगा। उस टाइप करें और 'Continue' चुनें।
- इसके बाद go to dashboard सेलेक्ट करें और अपना क्रेडिट स्कोर जांचें।

चुनाव से पहले बदल गए आपके शहर में पेट्रोल- डीजल के दाम, आज यहां इतने रुपये सस्ता मिल रहा फ्यूल

पेट्रोल और डीजल देश भर के अलग-अलग शहरों में अब सस्ता हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार की ओर से फ्यूल की कीमतों पर बड़ी राहत मिली है। इसी कड़ी में सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार 18 मार्च के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। बता दें फ्यूल की कीमतों पर रोजाना सुबह 6 बजे नया अपडेट जारी होता है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सोमवार, 18 मार्च के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं।

घर से बाइक या कार लेकर निकल रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी होना जरूरी है। बता दें, पेट्रोल और डीजल अब लगभग हर शहर में पहले के मुकाबले सस्ता मिल रहा है-

चार महानगरों में फ्यूल के ताजा दाम

राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.15 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

जगन मोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश और लेफ्ट के केरल में सबसे महंगे पेट्रोल-डीजल, जानिए किन राज्यों में सस्ता है रेट

अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट्स

नोएडा:पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम:पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु:पेट्रोल 99.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.93 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़:पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद:पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ: पेट्रोल 94.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर

सोना-चांदी के नए दाम हुए जारी, वायदा बाजार में ऐसा रहा दोनों धातुओं का हाल

सोना- चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। सोमवार के कारोबारी दिन सोना और चांदी वायदा बाजार में सस्ता हुआ है। सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 82 रुपये गिरकर 65460 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0 .25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2156 .10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली। सोमवार के कारोबारी दिन के लिए सोना-चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत में 10 रुपये की मामूली कटौती के साथ 66140 रुपये रही। वहीं, आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमत 66,150 रुपये प्रति दस ग्राम रही। चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत 77,000 रुपये प्रति किलो रही।

वायदा कारोबार की बात करें तो आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 82 रुपये कम हुई है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत 128 रुपये कम हुई है।

कम मांग से सोने के वायदा भाव में गिरावट

सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 82 रुपये गिरकर 65,460 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 82 रुपये या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,460 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 13,556 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,156.10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

चांदी वायदा गिरावट के साथ 75,522 रुपये प्रति किलोग्राम पर

सोमवार को चांदी की कीमत 128 रुपये गिरकर 75,522 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, मई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 26,060 लॉट के कारोबार में 128 रुपये या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,522 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25.31 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट्स

गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के रेट्स-

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,020 रुपये पर है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,870 रुपये पर है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,870 रुपये पर है।

चेन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,440 रुपये पर है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,870 रुपये पर है।

80सी के तहत टैक्स बचाना है, तो इन पांच योजनाओं में आंख बंद करके लगा दें पैसे

परिवहन विशेष न्यूज

टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन 80C काफी अहम है। इसके तहत निवेश के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं। अगर आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स छूट का लाभ तो मिलेगा ही साथ में आपका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित होगा। आइए टैक्स बचाने वाली स्कीमों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली : हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहता है। इसके लिए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश सबसे अच्छा विकल्प रहता है। इससे आपका टैक्स तो बचता ही है, साथ में आपका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित होता है।

टैक्स बचाने के लिहाज से इनकम टैक्स का सेक्शन 80C काफी अहम है। इसमें निवेश के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं। आइए हम आपको टैक्स बचाने वाली 5 स्कीमों के बारे में बताते हैं।

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर बच्चों के नाम से खोले PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, माता-पिता या भाई-बहन के अकाउंट में निवेश पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर रकम निकासी पर भी टैक्स छूट मिलती है।

2. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)

ELSS यूनिट में तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है यानी अब तीन साल के भीतर निवेश वाली रकम नहीं निकाल सकते। इसलिए यूनिट बेचने पर होने वाले फायदे पर आपको टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ता। निवेशक को मिलने वाला डिविडेंड भी टैक्स-फ्री रहता है। 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है। इसमें आप एकमुश्त या फिर SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं।

3. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)

यूलिप असल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट का मिला-जुला रूप है। इसमें आप जो प्रीमियम देते हैं, उसका एक हिस्सा जीवन बीमा कवर के लिए जाता है। वहीं, बचा हुआ हिस्सा रिटर्न के लिए किसी फंड में निवेश कर दिया जाता है। यूलिप में प्रीमियम की पूरी रकम पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

4. पांच साल के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट

इसे अमूमन इनकम टैक्स (Income Tax) सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश को आप पांच साल से पहले भुना नहीं सकते। हालांकि, इसमें ब्याज पर टैक्स चुकाना होता है।

5. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

NSC को टैक्स बचाने के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है। यह पांच साल में मैच्योर होता है। इसमें भी 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें भी ब्याज पर टैक्स देना होता है। हालांकि, शुरुआती वर्षों के ब्याज को NSC में निवेश समझा जाता है। ऐसे में उस पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

चीन ने भी मानी अग्नि-5 की ताकत, ग्लोबल टाइम्स

भारत अब मिसाइल टेक्नॉलजी का बड़ा खिलाड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अग्नि-5 मिसाइल टेस्ट पर उसने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक साथ कई सैटेलाइटों के परीक्षण को भी सराहा है। अग्नि-5 मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल एक बार में कई लक्ष्य भेद सकती है ,पूरा चीन होगा इसकी जद में। भारत इस मिसाइल तकनीक(MIRV)का उपयोग करने में सक्षम राष्ट्रों के कुछ चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। अभी तक ये तकनीक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास ही थी । चीनी मीडिया ने लिखा, ₹हमें एक वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक परिपक्व हो गई है, क्योंकि भारत एक रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है।

बाबा मस्त राम जी वॉलीबॉल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया

अमृतसर (साहिल बेरी) हरसिमरनदीप के नेतृत्व में मस्त रामजी वॉलीबॉल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सिंह संधू, अमृतपाल सिंह, सुखराज सिंह। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन अध्यक्ष सुविंदर सिंह संधू ने रिबन काटकर और गुब्बारे उड़ाकर किया। टूर्नामेंट की विजेता टीमों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष संधू ने कहा कि यह आयोजन श्रद्धालुओं के सहयोग से हर वर्ष मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज 19 मार्च को 51 श्री अखंड पाठ साहिब की पहली शृंखला के बाद 51 श्री अखंड पाठ साहिब की दूसरी शृंखला दोबारा शुरू की जाएगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु घर में हाजिरी लगाएंगे। इसी प्रकार, 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च और 27 मार्च तक श्री अखंड पाठ साहिब की अलग-अलग श्रृंखलाओं के बाद कुल 255 श्री अखंड पाठ साहिब आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 23, 24, 25 और 26 मार्च को दीवान सजाया जाएगा. विजेता टीमों को नकद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरभजन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंबरदार, अवतार सिंह सरकारिया उपाध्यक्ष, परमिंदर सिंह संधू सचिव, कुलवंत सिंह सरकारिया महासचिव, दविंदर सिंह संधू प्रचार सचिव, जत्थेदार मेजर सिंह सरकारिया ऑडिटर, सुरजीत सिंह स्टोर कीपर, अमनदीप सिंह ख्यालिया कोषाध्यक्ष, सुखबीर सिंह सोनी पूर्व कौंसलर, हरसिमरनदीप सिंह संधू, दिलबाग सिंह संसरिया, बग्गा सिंह, मंजीत सिंह झंड, सुरजीत सिंह संधू, अवतार सिंह संधू, पाल सिंह संधू, बलदीप सिंह, हरदयाल सिंह संधू, रघबीर सिंह संधू (सभी सदस्य समिति), खुशबीर सिंह आदि मौजूद रहे।

शक्ति' के लिए जान जोखिम में डाल दूंगा: नरेन्द्र मोदी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDI पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन की पहली रैली मुंबई में हुई और उन्होंने अपना घोषणापत्र जारी किया. उनका कहना है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है। पीएम ने कहा- 'एक तरफ वो लोग हैं जो शक्ति के विनाश की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं. 4 जून को यह प्रतियोगिता होगी कि कौन शक्ति को नष्ट कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। INDI गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता के खिलाफ है. मेरे लिए हर माँ, बेटी और बहन 'शक्ति' का रूप है। मैं उसकी पूजा करता हूं. मैं विपक्ष की चुनौती स्वीकार करता हूं. मैं उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा ।

पीओके का भारत में होगा विलय : अमित शाह

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय की घड़ी नजदीक आ गई है. पीओके को वापस लेने के लिए भारत की तैयारी पूरी होने की बात कही जा रही है. दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने देश की संसद से लेकर यू.एन. तक में इसका ऐलान कर दिया है।

पीओके के लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद पीओके के लोग आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं. पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म से यहां के नागरिक इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ये पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी भारत में शामिल कर लिया जाए. पीओके के नागरिक जानते हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में उनके बच्चों को हथियार मिलेंगे, तो भारत की सरपरस्ती में उनके बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में भी दो बार यह कहा था कि पीओके का भारत में विलय तय है.इसके अलावा, पीओके के भारत में विलय के पीछे कुछ अन्य कारण भी है, जिसमें एक है पाकिस्तान की सेना कमजोर हो गई है, उसके पास अवैध कब्जे को संभालने की ताकत नहीं बची है। पीओके के मामले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग-थलग भी पड़ गया है, जिसके बाद शहबाज सरकार के अंदर बेचैनी है. कोई देश अब खुलकर पीओके के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है. पिछले दिनों पीएम मोदी ने श्रीनगर का दौरा भी किया था, उस दौरान जो तस्वीर सामने आई थी, उससे साफ जाहिर था कि अब जम्मू-कश्मीर में हालात बदल गए हैं. घाटी में लगातार हो रही तरक्की का पीओके के लोगों पर असर पड़ा है। अब आपकों याद कराते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस ऐलान की, जिससे पीओके के लोग जय-जय हिंदुस्तान करने लगे हैं. पीओके को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता ने दुश्मन पाकिस्तान को संकेत दे दिया है कि वो दिन अब दूर नहीं, जब कंगाली की कगार पर पहुंच चुके नापाक पाकिस्तान को अपनी करतूत का खामियाजा भुगतना होगा. मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जिस तरह कश्मीर में विकास की गंगा बहाई है. उसमें आज पीओके का हर नागरिक अपने भविष्य के सपने देख रहा है. पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और कहा जा रहा है कि पीओके की आजादी की तारीख भी तय हो गई है।

सरकार का ब्लू प्रिंट तैयार.. पीओके अब नहीं रहेगा सीमा पार 76 साल से हिंदुस्तान के जिस टुकड़े पर पाकिस्तान ने अत्याचार और शोषण की पराकाष्ठा पार की है. अब भारत के उस हिस्से में तिरंगा फहराने का वक्त नजदीक आ गया है. मोदी सरकार का अगला लक्ष्य कश्मीर का एकीकरण है और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता. अब एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि पीओके न सिर्फ हमारा है, बल्कि पीओके में रहने वाले सभी लोग भी भारत के ही हैं। अमित शाह ने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके के सभी लोग भारतीय हैं, पीओके के सभी हिंदू हमारे लोग हैं, पीओके के मुसलमान भी हमारे हैं. अमित शाह का यह बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए अटल है, अडिग है, क्योंकि पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान ने दगाबाजी से हथिया लिया था. बल्कि पीओके में भारत के प्राण हैं. पीओके को वापस लेना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, बल्कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर अमन की राह पर बढ़ रहा है. भारत का अभिन्न अंग बनकर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. नए भारत के इस नए कश्मीर को देखकर दुश्मनों का कलेजा जल रहा है. एक तरफ कश्मीर में फिर से वो नजारा लौट आया है, जिसके लिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. तो दूसरी ओर कश्मीर के दूसरे हिस्से यानि पीओके में विरोध की वो ज्वाला धधक रही है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। भारत में कश्मीर अमन बहाली के बाद विकास की नई ऊंचाई छू रहा है. तो दूसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. भारत में विलय की मांग उठा रहे हैं. वहीं अब भारत के लोगों को भी लगने लगा है कि जल्द ही पीओके भी अखंड भारत का हिस्सा बनने वाला है, जिसका जिक्र 6 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संसद में दिए बयान में भी किया था पीओके की भारत वापसी की पक्की वजह क्या है? यह वही पीओके है जिसे लेकर देश की संसद से लेकर विदेश के कई बड़े मंच तक भारत शपथ ले चुका है. भारत कह चुका है कि पीओके खाली करो. पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का होगा और पीओके की भारत वापसी का प्लान बहुत बड़ा है. इसके लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं. आइए, जानते हैं कि पीओके की भारत वापसी की पक्की वजह क्या है?

देश की संसद से लेकर यू.एन. तक में भारत पीओके को लेकर ऐलान कर चुका है पाक की सत्ता इतनी कमजोर है कि अवैध कब्जे को संभालने की उसकी ताकत नहीं बची है.

पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही से पीओके के लोगों के अंदर बेचैनी है। कोई देश अब खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं है, इससे पाकिस्तान अलग-थलग पड़ चुका है. जम्मू-कश्मीर में तरक्की का भी पीओके के लोगों पर बड़ा असर हुआ है और वो लोग अब जय-जय हिंदुस्तान करने लगे हैं।

कश्मीर की संपूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करना भारत का अगला मिशन अब भारत के लिए कश्मीर की संपूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करना ही अगला मिशन है और वो बिना पीओके हासिल किए पूरा नहीं हो सकेगा. वहीं, पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भारत का कद दुनिया में बढ़ा है. उसमें पीओके के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं. खुशहाल जिंदगी और आतंक से आजादी का जो सपना पीओके के लोग आंखों में संजोए हुए हैं. उसके लिए उनकी उम्मीद सिर्फ भारत पर टिकी है. वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा।

पीओके में आम हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आम हो चुके हैं, तो गिलगित बाल्टिस्तान तक लोग पाकिस्तानी सरकार के विरोध में सिर उठाने लगे हैं. ऐसे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को पहले की चेता चुके हैं कि अगर उसके हुक्मरानों और सेना के जुल्म बंद नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड-खंड हो जाएगा. वहीं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बन सकता है. वीके सिंह की मानें तो भारत के लोगों को सिर्फ धैर्य रखना है और पीओके तो भारत में अपने आप ही शामिल हो जाएगा।

पीओके को लेकर भारत का स्टैंड क्या है? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का स्टैंड क्या है, इसकी बानगी आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में भी देखने को मिल जाएगी। जिन्होंने साफ-साफ कहा था कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है. पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात पर चर्चा हो सकती है कि वो ये कि पाकिस्तान पीओके खाली कब करेगा। पाक अधिकृत कश्मीर में उठती विरोध की लपटें इस बात की साक्षी हैं कि पाकिस्तान के जुल्म से परेशान वहां के नागरिक अब भारत का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं. उसी अखंड भारत का, जिसका हिस्सा वो सदियों से रहे हैं. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों का रात की नींद और दिन का चैन छिन चुका है. क्योंकि अगर पीओके में विद्रोह की आग भड़कती है, तो ऐसा ज्वालामुखी फटेगा, जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को खाक कर देगा और पाक अधिकृत कश्मीर को उस अखंड भारत का हिस्सा बना देगा, जो इसका असली हकदार है।

HVPNL के कच्चे कर्मचारी हुए पक्के

हरियाणा विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड

हरियाणा के कर्मचारियों में भारी उत्साह और खुशियों की लहर।

परिवहन विशेष न्यूज। नए मुख्यमंत्री के द्वारा HKRN, Outsourcing के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के निर्णय के बाद हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर चल पड़ी है। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद विपक्षी खेमे में हड़कम्प है। कच्चे कर्मचारियों और कौशल रोजगार के तहत लगे कर्मचारियों को जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है। उनके नाम 16 मार्च 2024 तक मुख्य कार्यालय में मांगे गए है। हरियाणा सरकार द्वारा अब 5 साल से ज्यादा से कार्यरत कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बहुत अधिक कच्चे कर्मचारी है जो बीते लम्बे समय से सरकार से रेगुलर किए जाने की गुहार लगा रहे थे । अब नायब सैनी में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा कच्चे कर्मचारियों और HKRN कर्मचारियों को दी गई सौगात से हर तरफ खुशियो का माहौल है।

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Regd. Office: Shakti Bhawan, Plot No. C-4, Sector-6, Panchkula, 134109
Corporate Identity Number : U40101HR1997SGC033683
Website : www.hvpn.org.in, eMail : companysecy@hvpn.org.in
Correspondence eMail: seadmn2@hvpn.org.in
Telephone No.- 0172-2561931-38

Office Order No. 73/SEG-112/L-453 **Dated: 14.03.2024**

The Government of Haryana vide letter memo No. 6/50/2007-1GSI dated 03.08.2011 alongwith notification dated 29.07.2011 duly adopted by HVPNL vide memo No. Ch-11/NGE/G-1054/II dated 11.05.2012 has notified the policy for regularization of Group-C & D employees appointed/engaged on Adhoc/Contract/Work charged/Daily wages and Part Time basis. The conditions as per the policy are as under:-

Sr. No	Conditions
(i)	That the employee/ worker should have continued to work for not less than ten years as on 10.04.2006 and is still in service but not under over of the orders of the Courts or Tribunals, against duly sanctioned vacant posts. The period of continuous br... service should not be more than 90 days in a calendar year [as per amen... 17.01.2012].
(ii)	That the employee/worker possessed the minimum prescribed qualification fo... the date of appointment/engagement.
(iii)	That the concerned employee should have been appointed only after either his name has been sponsored by the Employment Exchange or has been appointed/engaged on the basis of recommendations made by the Departmental Selection Committee by inviting applications through advertisement against duly sanctioned vacant post.
(iv)	That the work and conduct of such, employee should have been throughout satisfactory and no disciplinary or criminal proceedings should be pending against him.
(v)	That the employee should be regularized against a sanctioned vacant post of relevant category

1/2

2. The condition of their engagement through employment exchange has been taken as redundant as per Hon'ble High Court judgement dated 22.04.2014 in CWP No. 11368 of 2012 titled as "Gian Chand and others Vs HVPNL & others" The operative part of the judgement is as under:-

"In view of the facts as mentioned above and also the facts that the petitioners are working for the last more than 15 years on part time basis, regular sanctioned posts as well as requirement of work is also there, the condition of appointment through employment exchange cannot be accepted at this stage. In case, the work and conduct of the petitioners has been found satisfactory during last years then they should have been considered for regularisation as per policy of the State Government which has been adopted by respondent Nigam but still their claim has been rejected only on the ground that they were not appointed through employment exchange.
Accordingly, the present petition is allowed and the respondents are directed to consider the case of the petitioners for regularisation on regular sanctioned posts within a period of three months from the date of receipt of certified copy of the order."

Above judgement dated 22.04.2014 of Hon'ble High Court was further upheld by Hon'ble Supreme Court of India vide judgment dated 07.01.2015 in SLP No. 31306 of 2014.

3. The particulars of the Part Time Workers who have completed the 10 years services as on 10.04.2006 (except condition of their engagement through employment exchange) and sanctioned vacant posts of Sweeper/Mali are available in HVPNL is as under:-

Sr. No.	Name (Sh/Smt.)	Father's/ Husband's Name	Post	Place of posting	DOB	Date of Engagement	Qualification at the time of engagement	Period of engagement upto 10.04.2006 Year	Month	Day	Details of break in service year wise	Category
1.	Chander Bhan	Sandal	PTS	66 kV S/Stn, Partap Steel Faridabad	20.10.1967	01.11.1983	NA	22	5	9	Nil	SC
2.	Saroj Bala	Vijay Kumar	PTS	66 kV S/Stn. A-2 Faridabad	25.10.1968	01.11.1990	NA	15	5	9	Nil	SC
3.	Darshana	Shyam	PTS	66kV S/S Jharsately (Faridabad)	20.07.1976	01.11.1993	NA	12	5	9	Nil	SC
4.	Savitri Devi	Ravinder	PTS	220 kV S/S Pali (Faridabad)	10.06.1976	01.03.1995	NA	11	1	9	Nil	SC
5.	Ram Rati	Hawa Singh	PTS	O/o AE/Transformer Oil Test Lab Hisar	12.03.1975	03.08.1990	Illiterate	15	8	8	Nil	SC
6.	Om Parkash	Ram Shankar	PTM	SDO/Civil Delhi	14.06.1970	21.07.1994	8th	11	8	9	Nil	SC
7.	Babu Ram	Sawaran Singh	PTS	66kV S/S Mathana	10.04.1975	07.07.1995	Primary	10	09	00	No	SC
8.	Karam Singh	Phool Singh	PTS	132kV S/S Assandh	22.03.1964	01.03.1996	Nil	10	1	10	No	SC

MBhalla

conditions as per the policy are as under:-

Sr. No	Conditions
(i)	That the employee/ worker should have continued to work for not less than ten years as on 10.04.2006 and is still in service but not under over of the orders of the Courts or Tribunals, against duly sanctioned vacant posts. The period of continuous break in such service should not be more than 90 days in a calendar year [as per amendment dated 17.01.2012].
(ii)	That the employee/worker possessed the minimum prescribed qualification for the post on the date of appointment/engagement.
(iii)	That the concerned employee should have been appointed only after either his name has been sponsored by the Employment Exchange or has been appointed/engaged on the basis of recommendations made by the Departmental Selection Committee by inviting applications through advertisement against duly sanctioned vacant post.
(iv)	That the work and conduct of such, employee should have been throughout satisfactory and no disciplinary or criminal proceedings should be pending against him.
(v)	That the employee should be regularized against a sanctioned vacant post of relevant category

1/2

2. The condition of their engagement through employment exchange has been taken as redundant as per Hon'ble High Court judgement dated 22.04.2014 in CWP No. 11368 of 2012 titled as "Gian Chand and others Vs HVPNL & others" The operative part of the judgement is as under:-

"In view of the facts as mentioned above and also the facts that the petitioners are working for the last more than 15 years on part time basis, regular sanctioned posts as well as requirement of work is also there, the condition of appointment through employment exchange cannot be accepted at this stage. In case, the work and conduct of the petitioners has been found satisfactory during last years then they should have been considered for regularisation as per policy of the State Government which has been adopted by respondent Nigam but still their claim has been rejected only on the ground that they were not appointed through employment exchange.
Accordingly, the present petition is allowed and the respondents are directed to consider the

नवीन ने पत्र लिखा

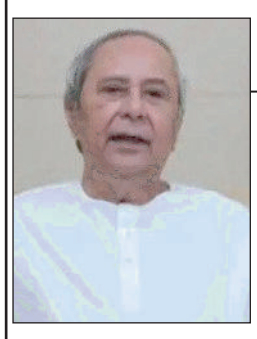

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर : मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के 4.5 करोड़ निवासियों को पत्र लिखा है ।हम साढ़े चार करोड़ लोगों के प्यार और अटूट विश्वास के साथ ओडिशा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाने के लिए आभारी हैं ।कुछ ही दिनों में प्रदेश की जनता देश की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रही है ।ओडिशा के 4.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। सबके सुख, दुःख, लाभ, कठिनाइयाँ सदैव सबके साथ हैं ।2036 तक ओडिशा सभी क्षेत्रों में नंबर 1 राज्य बनने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए हम इस संकल्प को और मजबूत करें और एक नए ओडिशा, एक मजबूत ओडिशा के निर्माण की दिशा में मिलकर

पारंपरिक वेशभूषा में घूमर नृत्य से सजा स्नेह मिलन

परिवहन विशेष न्यूज

बेंगलूरू: भैषाणा प्रवासी गांव का स्नेह मिलन समारोह दिनांक 17 मार्च रविवार को तुमकूर रोड स्थित रेजिडेंन्सी रिसॉर्ट में मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के साथ ही राज्य के अनेक प्रमुख शहरों से प्रवासी भैसाणा ग्रामवासी सपरिवार शामिल हुए। मां अम्बे की पूजा- अर्चना, मंगल आरती की गई। हरीराम सीरवी ने स्वागत किया। दिन भर चले स्नेह-मिलन समारोह में जहां गांव के बड़े-बुजुर्ग भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने में व्यस्त रहे। ढ़ोल के मधुर स्वर पर महिलाओं ने नृत्य से मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गेर मंडलों ने भाग लिया। रंग बिरंगी छतरिया एवं कलर पेपर से सुसज्जित डांडिया के साथ गैर नृत्य किया। बोहराराम सीरवी ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया ।भुण्डाराम देवासी ने बच्चों को

गिफ्ट उपहार वितरण किया। कार्यक्रम स्थल पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। जिसका भैसाणा गांव के सहपरिवारों ने लाभ लिया। इस अवसर पर पूनाराम सीरवी, बोहराराम सीरवी, भाकरराम देवासी, गजेंद्र सिंह जेतावत, प्रकाश प्रजापत, मानाराम सीरवी, नारायणलाल सीरवी, अनील सैन, हरीराम सीरवी, भीखसिंह राजपुरोहित सहित भैषाणा गांव के बड़ी संख्या में अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे।

केंद्र की नीतियों से त्रस्त है व्यापारी वर्ग-सिद्धार्थ बोहरा

कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

बेंगलूरू: व्यापारी वर्ग किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था का आधार स्तंभ होता है और ऐसे आधार स्तंभ के प्रति नरम रूख व समायोजन के भाव से आर्थिक व व्यवसायिक उनत्ती का मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से इस वर्ग पर कानून के नाम पर जुल्म ढाये जा रहे है। व्यापारी वर्ग के प्रति केंद्र सरकार की नीतिया आज सहयोगात्मक न होकर परेशान करने वाली है और इन्ही नीतियों के कारण हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग त्रस्त है। यह बात कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ बोहरा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग करने का रवैया सिर्फ बड़े व्यापारिक घरानों के साथ है जिसके कारण मध्यम व निम्न मध्यम व्यापारियों के व्यापार आज बंद होने की परिस्थिति में है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों के चेहरे पर पुनः पहले वाली मुस्कान लाना है तो केंद्र में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार लाना जरूरी है। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुद्दबीर अहमद व इरशाद अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग में समाहित मुस्लिम, जैन, सिक्ख, क्रिश्चियन, पारसी व बुद्ध के विकास व उद्धार के लिये प्रतिबद्ध है, और विशेषकर कर्नाटक में बसे उत्तर

भारतीय समुदाय के प्रति कांग्रेस की सोच हमेशा सहयोग की रही है। उन्होंने उत्तर भारतीय समुदाय से आने वाले लोकसभा चुनावों में भारी मतो से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का अनुरोध किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह चण्डोक, ग्रेसी लोबो, नासिर पाशा, अब्दुल अलीम इत्यादि भी मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**